facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 01 सितंबर 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 06 ● मूल्यः 5 रुपए

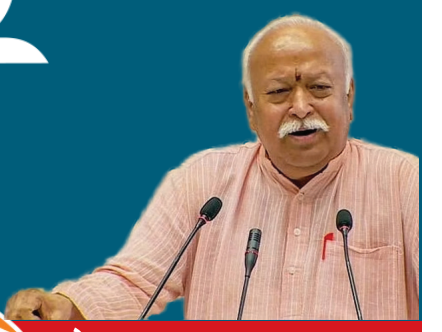

मोहन भागवत का 75...

मनुष्य में जब अहंकार आ जाता है तो उसका पतन हो जाता है। कई बार सेवादार में भी अकड़ आ जाती है जो उसके लिए हानिकारक होती है।

पेज-10-11

सद्गुरु वाणी

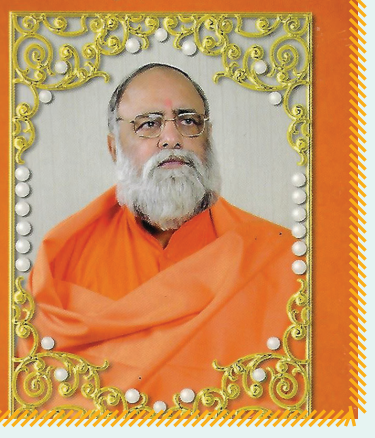

दिव्य पाठ प्रभु कृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है।यह बड़ा सहज और सरल है।

●

अपनी आय का जो अंश आप दान के रूप में निकालते हैं वह अंश बीज रूप में पनपता है। यही बीज आपके दुखों कष्टों और समस्याओं का समाधान करता है।

●

प्रार्थनाओं से जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का कभी हल नहीं होता। हम केवल अपनी समस्याओं से भगाने के लिए प्रवचनों का सहारा लेते हैं।

एससीओ समिट में भारत-चीन-रूस की तिकड़ी

क्या वाकई अमेरिका के लिए चुनौती?

@ भारतश्री ब्यूरो

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक इस बार सिर्फ कूटनीति का मंच नहीं बनी, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र भी रही। वजह थी – भारत, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं का एक साथ आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब एक ही मंच पर दिखे, तो दुनिया भर की निगाहें उसी पर टिक गईं। खासकर अमेरिका में यह तस्वीर चिंता का सबब बनी।क्योंकि ये तीनों ही देश हाल के वर्षों में अमेरिकी निशाने पर रहे हैं। कभी व्यापार को लेकर विवाद, कभी युद्ध को लेकर दबाव और कभी ऊर्जा सौदों पर खींचतान अमेरिका और इन तीनों देशों के रिश्ते तल्ख दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उनकी एकजुटता का संदेश वाशिंगटन को असहज कर गया।

प्रतिद्वंद्विता की लकीर गहरी

चीन और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्तों में हमेशा प्रतिस्पर्धा हावी रही है।कुछ महीने पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि चीनी छात्रों के वीज़ा रद्द किए जाएंगे।इसके साथ ही व्यापार को लेकर दोनों के बीच तीखी बयानबाजी और टैरिफ वॉर छिड़ गई।हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारते हुए कहा कि वे चीनी छात्रों को रोकना नहीं चाहते और चीन से व्यापार के जरिये अमेरिका को काफी मुनाफा हो रहा है।लेकिन यह नरमी ज्यादा देर तक नहीं चली। टेक्नोलॉजी, दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे मुद्दों पर दोनों की तल्खी फिर सामने आने लगी। अमेरिका को लगता है कि चीन वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका को चुनौती दे रहा है।

युद्ध ने बढ़ाई दूरी

रूस और अमेरिका के बीच का तनाव यूक्रेन युद्ध ने और गहरा कर दिया।अमेरिका बार-बार रूस पर प्रतिबंध लगाता रहा, उसके सहयोगियों को भी चेतावनी देता रहा कि वे रूस से कारोबार न करें।राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार पुतिन से मुलाकात की, जेलेंस्की को भी बातचीत के लिए बुलाया। उम्मीद जताई गई थी कि शायद कूटनीतिक रास्ते से युद्ध थमेगा।लेकिन हुआ उल्टा। रूस ने और तेजी से हमले शुरू कर दिए।इससे ट्रंप प्रशासन और दबाव में आया। अमेरिका ने सैन्य मदद, आर्थिक पैकेज और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाकर यूक्रेन के पक्ष को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन रूस की रणनीति ने अमेरिका को बार-बार असफल किया।

ऊर्जा और राजनीति की खींचतान

भारत और अमेरिका के रिश्ते भी हाल के दिनों में उतने सहज नहीं रहे, जितने पहले दिखाई देते थे।विवाद की बड़ी वजह बनी रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना। अमेरिका का आरोप है कि भारत इस कारोबार से मुनाफा कमाकर रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है।इसके अलावा ट्रंप कई बार भारत-पाकिस्तान तनाव में "मध्यस्थता" करने का दावा करते रहे। भारत ने हमेशा इसे नकारा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हो गए।अमेरिकी जुर्माने और व्यापारिक दबाव ने भी रिश्तों को प्रभावित किया।हालांकि रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक भरोसा उतना गहरा नहीं दिखता।

मोदी-जिनपिंग-पुतिन की मुलाकात

SCO समिट में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मौजूदगी सिर्फ औपचारिकता नहीं थी।तीनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और बातचीत से यह संदेश गया कि वे सहयोग के नए रास्ते तलाश सकते हैं।अमेरिका के लिए यह संकेत नकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि यह "त्रिकोणीय समीकरण" उसके वैश्विक हितों को चुनौती दे सकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत, चीन और रूस किसी साझा एजेंडे पर सहमत हो जाते हैं, तो यह पश्चिमी देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

क्यों परेशान हुआ अमेरिका?

अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन और रूस को रोकने के लिए भारत पर भरोसा करता रहा है। लेकिन अगर भारत भी रूस-चीन के करीब जाता है तो यह उसकी रणनीति के लिए झटका होगा।रूस से भारत का तेल आयात और चीन के साथ उसका विशाल व्यापार, अमेरिकी प्रतिबंधों और नीतियों को कमजोर कर सकता है।ब्रिक्स और SCO जैसे मंच अगर मजबूत होते हैं, तो पश्चिमी ब्लॉकों का असर घट सकता है।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार

अगस्त बना 13 साल का सबसे ठंडा महीना

कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा, कामकाजी लोगों और स्कूली बच्चों को हुई दिक्कत

@ मनीष पांडेय

दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर के समय कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कई जगहों पर दोपहर होते-होते दिन में ही अंधेरा छा गया।

मौसम में आए इस बदलाव ने जहाँ लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं ऑफिस जाने वाले कामकाजी लोगों और स्कूल से घर लौट रहे बच्चों के लिए परेशानी भी खड़ी कर दी।

नोएडा-गाजियाबाद में हल्की बरसात, दिल्ली में तेज बारिश

एनसीआर के अन्य शहरों नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार सुबह हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई थी। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। मंदिर मार्ग और सेंट्रल दिल्ली के अन्य हिस्सों में बारिश का असर साफ दिखाई दिया।अचानक हुई इस बारिश से लोग भीगते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे। कई जगह जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई।

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सोमवार से अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा।दरअसल, इस समय उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके चलते एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसका असर पूरे उत्तर-पश्चिम भारत पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक दिल्ली-एनसीआर के अलावा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

अगस्त में बना बारिश का नया रिकॉर्ड

इस बार अगस्त का महीना दिल्ली के मौसम के लिए खास साबित हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी में अगस्त 2023 (मान लो अभी की रिपोर्ट के अनुसार) अब तक 480.81 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा है।इससे पहले अगस्त 2010 में 455.1 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। जबकि अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड 1961 में दर्ज 583.3 मिमी बारिश का है। यानी इस बार का अगस्त उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के करीब पहुँच चुका है।

लगातार 14 दिन हुई बारिश

दिल्ली में अगस्त महीने में अब तक 14 दिन बारिश हुई है। लगातार बरसात ने राजधानी के मौसम को सामान्य से ठंडा बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस अगस्त का औसत अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले 13 साल में सबसे कम है।इसी तरह औसत न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा। इससे यह अगस्त 2012 के बाद सबसे ठंडा अगस्त साबित हुआ है।

बारिश से मिली राहत, पर बढ़ी परेशानियाँ

भारी बारिश ने जहाँ लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं समस्याएँ भी खड़ी की हैं।कई मुख्य सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक घंटों तक प्रभावित रहा।स्कूल की छुट्टी के समय हुई बारिश में बच्चे भीगते हुए घर पहुँचे।ऑफिस आने-जाने वालों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में रोशनी कम होने के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और बिजली कटौती की खबरें भी आईं।

मौसम विशेषज्ञों की राय

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मॉनसून की सक्रियता दिल्ली-एनसीआर में खास तौर पर दिख रही है। सामान्यतः अगस्त में इतनी लगातार बारिश नहीं होती। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का संगम राजधानी में भारी बारिश ला रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला रुक-रुककर जारी रहेगा। इससे सितंबर की शुरुआत भी ठंडी और सुहानी होने के आसार हैं।

किसानों और पर्यावरण पर असर

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस बारिश से खेती को भी लाभ मिला है। धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए यह बरसात वरदान साबित हुई है।साथ ही लगातार हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आई है। हवा में धूल और धुएं के कण धुल गए हैं, जिससे दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधरी है।

13 साल का सबसे ठंडा अगस्त

मौसम विभाग के आँकड़े बताते हैं कि इस बार का अगस्त पिछले 13 साल का सबसे ठंडा महीना रहा। अगस्त का महीना इस बार दिल्लीवासियों के लिए यादगार बन गया। झमाझम बारिश ने जहाँ लोगों को राहत दी, वहीं परेशानियाँ भी बढ़ा दीं। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस बार की बारिश ने कई साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।

SCO शिखर सम्मेलन में भारत की बड़ी जीत

पहलगाम हमले की निंदा पर बनी सहमति, मोदी-पुतिन की कार में हुई गोपनीय बातचीत, चीन में SCO शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन भारत के लिए अहम साबित हुआ

@ अजयवीर

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के दूसरे दिन भारत को वह सफलता मिली, जिसका इंतज़ार लंबे समय से था। चीन में आयोजित इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और उन्हीं की मौजूदगी में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। यह पहली बार है जब SCO के साझा घोषणा पत्र में इस हमले का ज़िक्र हुआ और आतंकवादियों को सजा दिलाने की बात कही गई।भारत ने इस मुद्दे को लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया था। दरअसल, इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। भारत ने इस घटना को 'मानवता पर हमला' बताया था और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

पहले SCO बैठक में नहीं था जिक्र, भारत ने जताई थी नाराजगी

यह भी गौर करने वाली बात है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान SCO घोषणापत्र में पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था। उस समय भारत ने कड़ा विरोध जताया था और दस्तावेज़ पर साइन करने से इनकार कर दिया था।लेकिन इस बार भारत की कूटनीति रंग लाई और सभी सदस्य देशों ने न सिर्फ हमले की निंदा की बल्कि आतंकियों और उनके मददगारों को सजा दिलाने की बात भी मान ली। पाकिस्तान की मौजूदगी में यह सहमति भारत की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है।

मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह आतंकवाद का सबसे बुरा रूप है, जहां निर्दोषों को निशाना बनाया जाता है।मोदी ने साफ सवाल उठाया, "कुछ देशों को आतंकवाद का खुला समर्थन करने की छूट आखिर क्यों दी जा रही है?" उनका इशारा पाकिस्तान की ओर माना जा रहा है, जो लंबे समय से आतंकी संगठनों को समर्थन देने के आरोप झेल रहा है।

मोदी और पुतिन की कार डिप्लोमेसी

सम्मेलन के बाद एक और दिलचस्प और अहम घटना हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए साथ निकले। खास बात यह रही कि पुतिन अपनी लग्जरी कार AURUS लिमोज़िन में मोदी को लेकर गए।रिपोर्ट्स के मुताबिक, रास्ते में दोनों नेताओं ने लगभग 45 मिनट तक गोपनीय बातचीत की। होटल पहुंचने के बाद भी वे तुरंत कार से नहीं उतरे और करीब एक घंटे तक वहीं चर्चा करते रहे।रूस के रेडियो चैनल Vesti FM और क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बैठक की पुष्टि की। मॉस्को के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कार में हुई यह चर्चा बेहद अहम थी, जिसमें उन मुद्दों पर बात हुई जिन्हें सार्वजनिक तौर पर साझा करना मुमकिन नहीं था।

पुतिन ने SCO को बताया ग्लोबल साउथ का मंच

भारत के साथ बैठक में पुतिन ने SCO की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह संगठन ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों को एकजुट करने का एक बड़ा मंच है।पुतिन ने यह भी याद दिलाया कि दिसंबर 2025 में भारत-रूस संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा मिले 15 साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बहुआयामी रिश्ते और मजबूत होंगे।

यूक्रेन जंग पर भी हुई चर्चा

भारत और रूस के बीच बातचीत का एक अहम हिस्सा यूक्रेन युद्ध भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।मोदी ने हाल ही में हुए शांति प्रयासों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि सभी पक्ष रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा – "इस संघर्ष को खत्म कर स्थायी शांति का रास्ता निकालना जरूरी है, यह पूरी मानवता की मांग है।"

मुश्किल दौर में भी भारत-रूस साथ खड़े रहे

मोदी ने अपनी बातचीत में यह भी याद दिलाया कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। दोनों देश हमेशा मुश्किल हालात में एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।उन्होंने कहा कि यह सहयोग न सिर्फ दोनों देशों की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अहम भूमिका निभाता है।

भारत की कूटनीति का बड़ा असर

SCO शिखर सम्मेलन से यह साफ हो गया कि भारत की कूटनीति एशियाई राजनीति में लगातार असरदार होती जा रही है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरे में लाना और उसकी मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा करवाना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है।इसके साथ ही रूस के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना भी भारत की विदेश नीति की कामयाबी है। पुतिन और मोदी की कार में हुई गोपनीय बातचीत ने यह संदेश दिया है कि दोनों देशों के बीच भरोसा गहरा है और भविष्य की दिशा पर गंभीर मंथन जारी है।चीन में हुई इस बैठक ने साफ कर दिया कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश है।

लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों का इम्तिहान

केंद्र दूर बने तो परेशानी भी बढ़ी, 6 और 7 सितंबर को होगी परीक्षा

@ शोभित यादव

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) इस साल 6 और 7 सितंबर को होने जा रही है। दो दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके जरिए उन्हें आगे ग्रुप 'C' की भर्तियों के लिए पात्रता मिलेगी।परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए यह अहम मौका है, क्योंकि पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैध रहता है। यानी, एक बार परीक्षा पास करने पर अभ्यर्थी तीन साल तक विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं।

जारी हुई सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड का इंतजार

आयोग की ओर से परीक्षा से पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। इससे अभ्यर्थियों को यह जानकारी मिल गई है कि उनका परीक्षा केंद्र किस जिले में है। अब सभी को एडमिट कार्ड का इंतजार है। संभावना है कि 1 सितंबर तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर डाउनलोड कर सकेंगे।

किन भर्तियों के लिए जरूरी है पीईटी?

यूपी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए पीईटी अनिवार्य होगा। यानी जो अभ्यर्थी पीईटी पास करेंगे, वही आगे इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे।

- राजस्व लेखपाल
- ग्राम पंचायत अधिकारी
- सहायक बोरिंग टेक्नीशियन
- वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक
- आईटीआई अनुदेशक
- सम्मिलित तकनीकी सेवा
- एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग
- एक्स-रे टेक्नीशियन
- एग्रीकल्चर असिस्टेंट
- जूनियर असिस्टेंट (राजस्व विभाग)
- अकाउंटेंट व ऑडिटर
- गन्ना विभाग में सर्वेयर

यानी पीईटी अब ग्रुप 'C' की भर्तियों का मुख्य द्वार बन चुका है।

अभ्यर्थियों की नाराजगी कितनी जायज?

परीक्षा की तैयारियों के बीच सबसे बड़ी दिक्कत परीक्षा केंद्रों को लेकर सामने आई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए गए हैं। इससे उम्मीदवारों में नाराजगी है।लोकल 18 की टीम जब छात्रों से बात करने पहुंची तो उन्होंने साफ कहा, "यह परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई करने वाली है, इसमें मेरिट का सीधा दबाव नहीं है। ऐसे में आयोग को चाहिए था कि कम से कम परीक्षा केंद्र नजदीकी बनाए जाते। लेकिन इस बार केंद्र बहुत दूर बने हैं, जिससे छात्रों को पहुंचना मुश्किल हो रहा है।"

"लोक सेवा आयोग से सीख ले आयोग"

लखनऊ के रहने वाले अभ्यर्थी पंकज पांडे ने बातचीत में कहा, "यूपीएसएसएससी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) से सीखनी चाहिए। लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 75 जिलों में सफलतापूर्वक कराई थी। जब इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन इतने जिलों में हो सकता है, तो पीईटी का केंद्र भी पास-पड़ोस में क्यों नहीं बनाया गया?"

पंकज ने सरकार से यह भी मांग की कि अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड ही बस का टिकट बना दिया जाए ताकि उन्हें आने-जाने में सुविधा मिले। अगर संभव हो तो ट्रेनों में भी मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाए।

"रेलवे की तरह चरणबद्ध परीक्षा होती तो बेहतर रहता"

गाजियाबाद से आई छात्रा अंजली ने कहा, "रेलवे की परीक्षाएं कई चरणों में होती हैं। उसी तरह पीईटी को भी चरणबद्ध तरीके से आयोजित करना चाहिए था। वैसे भी इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान है। अगर परीक्षा चरणों में होती तो छात्रों को लंबी दूरी तय करने की परेशानी नहीं होती।"

कई छात्रों ने बताया कि परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से यात्रा का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी परेशान हैं।कम से कम 3,000 रुपये सिर्फ आने-जाने में लग जाएंगे। यह हर छात्र के लिए संभव नहीं है। कई तो आर्थिक बोझ की वजह से परीक्षा देने ही नहीं जा पाएंगे।सरकार का कहना है कि परीक्षा केंद्रों का चयन तकनीकी प्रक्रिया से किया गया है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आयोग का दावा है कि इतनी बड़ी परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या सीमित है, इसलिए हर जिले में केंद्र बनाना संभव नहीं था।

अहम है यह परीक्षा

यूपी पीईटी परीक्षा इस मायने में अहम है कि यह राज्य में ग्रुप 'C' की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाती है। पहले हर पद के लिए अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षा होती थी, जिससे उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देनी पड़ती थी। अब पीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी तीन साल तक सभी ग्रुप 'C' की भर्तियों में सीधे शामिल हो सकते हैं। यूपी पीईटी परीक्षा ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी की उम्मीद दी है। लेकिन परीक्षा केंद्र दूर बनाए जाने से छात्रों में निराशा भी है।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 01 सितंबर 2025, विक्रम संवत 2080

क्या यह लोकतंत्र की जगह तानाशाही नहीं

मैंने आज सुबह एक राष्ट्रपति के बदलाव के संबंध में सुझाव दिया था । दो प्रश्न महत्वपूर्ण उठे हैं । पहला प्रश्न यह उठाया गया है की क्या यह लोकतंत्र की जगह तानाशाही नहीं है। मैं इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह विचार किया। आप बताइए मेरे सुझाव में क्या तानाशाही है । भारत में संविधान रहेगा तो जैसा है वैसा रहेगा सिर्फ बदलाव इतना किया गया है की जो संविधान राजेंद्र बाबू के समय में लागू था वह संविधान मान्य होगा उसके बाद जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों पर राष्ट्रपति फिर से विचार कर सकते हैं । यदि मान लीजिए कि ऐसे कुछ संशोधन राष्ट्रपति हटा भी देते हैं तो फिर से उसको संसद लागू कर सकती है। यदि उचित समझा जाएगा तो ग्राम सभाओं की भी स्वीकृति ली जाएगी अन्यथा फिर से लागू किया जा सकता है कुछ भी किया जा सकता है। यदि हम प्रारंभिक संविधान को लागू कर देते हैं तो इसमें तानाशाही कहां है क्या शुरुआत में तानाशाही थी। मेरे सुझाव में भागवत जी को क्या विशेष अधिकार मिल गया जिस कारण से आपको तानाशाही दिखने लग गई। प्रधानमंत्री वही है मंत्रिमंडल वही है सांसद वही है चुनाव प्रणाली वही है सब कुछ तो वही है केवल बदलाव यह हुआ है की जैसा शुरुआत में था वहां से आगे फिर से शुरुआत होगी । बस इसलिए मुझे तो इसमें किसी प्रकार की तानाशाही दिखती ही नहीं है। एक दूसरा प्रश्न उठा की मोहन भागवत ही क्यों। मैं इस प्रश्न पर भी विचार किया इस स्थान पर मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र तो अब 87 वर्ष हो रही है वैसे भी मैं संन्यास आश्रम में हूं इसलिए इस प्रकार की कोई संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेदारी निभा नहीं सकता । तब फिर प्रश्न उठता है कि यदि मैं नहीं तो कौन। मुझे मोहन भागवत का नाम समझ में आया क्योंकि वहां शपथ लेने के 15 दिन के अंदर भागवत जी को जनमत संग्रह से सहमति भी लेनी पड़ेगी और वर्तमान भारत में मुझे मोहन भागवत को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है जो जनमत संग्रह में बहुमत प्राप्त कर लेगा। फिर भी यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो आप नाम सुझा सकते हैं अथवा जनमत संग्रह के समय वह आदमी भी 15 दिन के अंदर अपना नाम दे सकता है इसमें आपको क्या दिक्कत है । तो मेरे हिसाब से तो वर्तमान भारत में मोहन भागवत को छोड़कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने लायक कोई और नहीं दिखता है एक प्रश्न और उठा कि हम यह जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को क्यों ना दे दे तो मेरे विचार में अभी नरेंद्र मोदी को यह जिम्मेदारी देना उचित नहीं है क्योंकि अभी हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि नरेंद्र मोदी किस दिशा में जाएंगे लेकिन मोहन भागवत की हम गारंटी दे सकते हैं कि वह किस दिशा में जाएंगे इसलिए फिर दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो फिर हम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बना कर और प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे इसलिए मेरे विचार से सब कुछ आराम से चलने दीजिए और मैंने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पर आप सब लोग सर्वसम्मति से स्वीकृति दीजिए।

बजरंग मुनि

भारत- अमेरिका रिश्तों की कसौटी पर ट्रंप का बयान

@ **अनुराग पाठक**

अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा से वैश्विक राजनीति के सबसे अहम अध्यायों में गिने जाते रहे हैं। कभी यह रिश्ता तकनीक और लोकतांत्रिक मूल्यों की साझेदारी से परिभाषित होता है, तो कभी व्यापारिक मतभेद और रणनीतिक असहमतियाँ इसमें तनाव ले आती हैं। सोमवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बयान इसी कड़ी का नया अध्याय है। ट्रम्प ने दावा किया कि भारत ने अब अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन यह कदम बहुत देर से उठाया गया है। उनके अनुसार भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर इतने ऊंचे टैरिफ लगाए कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में टिक पाना मुश्किल हो गया, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों के लिए खुला बाजार बनाए रहा। ट्रम्प के शब्दों में यह रिश्ता पूरी तरह से "एकतरफा आपदा" रहा है।

ट्रम्प की टिप्पणी केवल व्यापारिक असंतुलन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भारत के रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र की प्राथमिकताओं को भी कठघरे में खड़ा किया। ट्रम्प का आरोप है कि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा रूस से पूरा करता है, चाहे वह तेल हो या फिर सैन्य उपकरण। यह बात उनके लिए इसलिए असहज है क्योंकि अमेरिका इन क्षेत्रों में भारत के लिए बड़ा साझेदार बनने का इच्छुक रहा है। लेकिन भारत ने अपने हितों के मद्देनज़र रूस को तरजीह दी। ट्रम्प ने इसे "सालों पुरानी समस्या" बताते हुए कहा कि भारत को पहले ही टैरिफ कम करना चाहिए था और अमेरिकी साझेदारी को ज्यादा महत्व देना चाहिए था।

यह बयान उस समय सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होकर रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके थे। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के इस परिदृश्य ने ट्रम्प की टिप्पणी को और ज्यादा राजनीतिक और सामरिक रंग दे दिया। अमेरिका में इस बयान को ऐसे भी देखा जा रहा है कि ट्रम्प अपने चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत पर सख्ती दिखाना चाहते हैं, ताकि वे घरेलू मतदाताओं को संदेश दे सकें कि उनकी प्राथमिकता अमेरिकी उद्योग और हित हैं।

लेकिन अमेरिकी राजनीति के भीतर एक दूसरा स्वर भी मौजूद है। मौजूदा विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रम्प से बिल्कुल उलट बयान दिया। उन्होंने भारत-अमेरिका की साझेदारी को 21वीं सदी की सबसे अहम और खास साझेदारी करार दिया। रुबियो ने कहा कि तकनीक, रक्षा, संस्कृति और कारोबार जैसे क्षेत्र दोनों देशों के रिश्तों को नई गहराई दे रहे हैं। उनके अनुसार यह दोस्ती केवल रणनीतिक समझौतों पर नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भरोसे और सम्मान पर आधारित है। यह दृष्टिकोण अमेरिकी कूटनीति के उस पक्ष को सामने लाता है, जो भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक साझेदार के रूप में देखना चाहता है।

ट्रम्प के सलाहकार पीटर नवारो ने इस बहस में और ज्यादा विवादास्पद रंग भर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उससे मुनाफा कमा रहा है और इस प्रक्रिया में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध जारी रखने के लिए आर्थिक ताकत मिल रही है। नवारो की सबसे तीखी टिप्पणी भारतीय ब्राह्मणों को लेकर थी। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं और इसका खामियाजा पूरा भारत चुका रहा है। यह टिप्पणी न केवल तथ्यात्मक रूप से कमजोर लगती है बल्कि सामुदायिक विभाजन पैदा करने वाली भी कही जा सकती है। इससे यह साफ हो जाता है कि अमेरिका के कुछ नीति-निर्माता भारत पर दबाव बनाने के लिए रूस के मुद्दे का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

ट्रम्प ने खुद भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का दावा किया है। उनके अनुसार इसमें 25 प्रतिशत बेस टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क शामिल है। वे कहते हैं कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में बेच रहा है और इस प्रक्रिया से पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतने ऊंचे टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों पर भी बोझ नहीं डालते? क्या इससे अमेरिका की ही प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम नहीं होती? यह पहलू ट्रम्प के बयान में पूरी तरह अनुपस्थित है।इन सारे आरोपों और तर्कों के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट इस पूरे विवाद को बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प और मोदी के बीच तनाव की असल वजह न तो तेल है और न ही टैरिफ, बल्कि ट्रम्प की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। रिपोर्ट का दावा है कि ट्रम्प ने 17 जून को मोदी से कहा था कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि भारत से भी उन्हें ऐसा ही समर्थन मिलना चाहिए। जब मोदी ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो ट्रम्प नाराज हो गए। अगर यह दावा सच है तो भारत पर ट्रम्प की नाराजगी की जड़ व्यापार या कूटनीति नहीं बल्कि उनकी निजी ख्वाहिश है।

जुबानी तीर

"यह सच है कि ऊपरी जाति के कॉरपोरेट घराने रूसी तेल को सस्ते दामों पर खरीदकर उसका परिष्करण कर बेच रहे हैं, लेकिन सामान्य भारतीय इससे लाभान्वित नहीं हो रहा है।पिछड़े वर्गों और दलितों को कॉरपोरेट क्षेत्र में स्थापित होने में शायद सौ साल तक लग जाएंगे।

कांग्रेस नेता उदित राज (पूर्व सांसद,कांग्रेस नेता)

"नवारो द्वारा ब्राह्मणों का उल्लेख, "यद्यपि अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में यह एक समृद्ध वर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द हो सकता है", लेकिन भारत के सन्दर्भ में यह जानबूझ कर किया गया हमला है। इस बयान से धर्म और जाति की संवेदनशीलता को ठेस पहुंचती है।

प्रियंका चतुर्वेदी (संसद सदस्य)

"भारत रूस से तेल खरीदकर केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार को स्थिर बनाए रख रहा है और संभावित $200 प्रति बैरल के उछाल को रोका है। भारत कानूनी मानदंडों के तहत तेल खरीद रहा है, और इस बात से कोई लाभ नहीं उठा रहा है।

हरदीप सिंह पुरी (केंद्रीय तेल मंत्री):

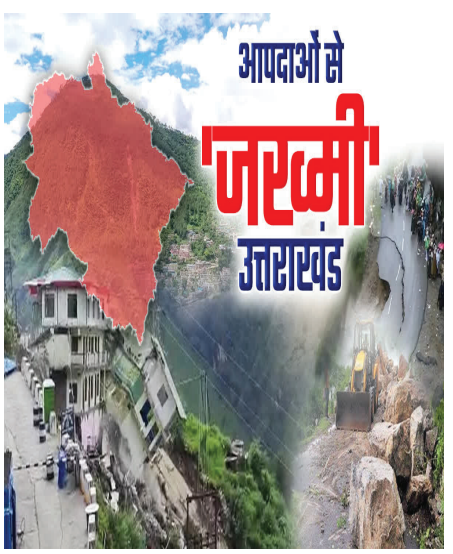

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

सर्वाइकल पेन का आयुर्वेदिक इलाज

जड़ों से उपचार की राह

@ डॉ महिमा मक्कर

आज की तेज़-रफ्तार ज़िंदगी में सर्वाइकल पेन (गर्दन का दर्द) एक आम समस्या बन गई है। ऑफिस में लगातार कंप्यूटर के सामने बैठना, मोबाइल का अधिक इस्तेमाल, गलत सोने की आदतें और व्यायाम की कमी – ये सब कारण बनते हैं इस दर्द के। सर्वाइकल पेन सिर्फ़ गर्दन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह कंधों, बाजुओं और सिर तक दर्द फैला सकता है। कई बार मरीज को चक्कर, सिरदर्द और हाथों में झनझनाहट जैसी शिकायतें भी होने लगती हैं।

एलोपैथिक दवाइयाँ अक्सर तुरंत आराम तो देती हैं, लेकिन लंबे समय तक इनके साइड-इफेक्ट भी सामने आते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक इलाज एक सुरक्षित और स्थायी विकल्प बनकर उभरता है। आयुर्वेद शरीर को सिर्फ़ लक्षणों से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों से उपचार करने में विश्वास करता है।

सर्वाइकल पेन क्यों होता है?

आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ तीन दोष होते हैं। जब इनमें असंतुलन होता है, तो बीमारियाँ जन्म लेती हैं।सर्वाइकल पेन का मुख्य कारण वात दोष का बढ़ना माना जाता है।गलत बैठने की मुद्रा, लगातार झुककर काम करना, ठंडी हवा या ज्यादा तनाव भी इस समस्या को बढ़ा देता है।हड्डियों और नसों में जकड़न आ जाती है, जिससे दर्द और अकड़न महसूस होती है।

आयुर्वेदिक इलाज के मुख्य उपाय

1. पंचकर्म चिकित्सा

पंचकर्म आयुर्वेद की खास चिकित्सा पद्धति है। इसमें शरीर से विषैले तत्व निकालकर रोगों की जड़ पर असर किया जाता है।

अभ्यंग (तेल मालिश): गर्म औषधीय तेल से मालिश करने से नसें खुलती हैं और रक्त संचार बेहतर होता है।

स्वेदन (स्टीम थेरेपी): भाप से स्नायु और मांसपेशियों की जकड़न कम होती है। औषधीय घी या तेल को पीठ और गर्दन पर विशेष तरीके से रखा जाता है, जिससे तुरंत आराम मिलता है।

2. औषधीय तेल और लेप

महारास्नादि क्वाथः वात रोगों में उपयोगी काढ़ा।गंधरास तेल या महास्नान तेलः मालिश करने पर दर्द और सूजन दोनों में आराम।निर्गुंडी और अश्वगंधाः

इनकी पत्तियों का लेप गर्दन पर लगाने से सूजन और अकड़न कम होती है।

3. घरेलू नुस्खे

हल्दी वाला दूधः हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो सूजन और दर्द को कम करता है।

लहसुन की कलीः सुबह खाली पेट 2-3 कच्ची लहसुन की कलियां खाने से वात दोष नियंत्रित होता है।

मेथी दानाः रातभर भिगोकर सुबह चबाने से जोड़ों और हड्डियों को मजबूती मिलती है।

4. योग और प्राणायाम

योगासन और प्राणायाम से शरीर लचीला होता है और मानसिक तनाव भी घटता है।

भुजंगासन (सर्पासन): रीढ़ को लचीला बनाता है।

मकरासन: गर्दन और पीठ के दर्द में आराम देता है।

शशांकासन: नसों पर दबाव कम करता है।

अनुलोम-विलोम व कपालभाति: मानसिक तनाव और रक्त संचार दोनों को संतुलित करते हैं।

5. आहार और जीवनशैली

भारी, तैलीय और जंक फूड से बचें।

हरी सब्ज़ियाँ, ताज़े फल, दूध और दालें अधिक खाएं।

अधिक देर तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें।

रोज़ाना कम से कम आधा घंटा टहलने की आदत डालें।

सोते समय गर्दन के नीचे न तो बहुत ऊँचा तकिया रखें और न ही बहुत नीचा।

आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद का संतुलन

आधुनिक चिकित्सा पेन किलर और फिजियोथेरेपी के ज़रिए लक्षणों पर काम करती है। वहीं आयुर्वेद शरीर में संतुलन लाकर स्थायी उपचार देता है। दोनों को साथ अपनाने से और भी बेहतर परिणाम मिलते हैं।आयुर्वेदिक चिकित्सक मानते हैं कि अगर शुरुआत में ही रोगी प्राकृतिक उपचार अपनाए, तो यह समस्या गंभीर रूप नहीं लेती। पंचकर्म और नियमित योगासन से न सिर्फ़ दर्द में राहत मिलती है, बल्कि भविष्य में इसका खतरा भी कम हो जाता है।सर्वाइकल पेन आज के दौर की जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है। दवाओं से तुरंत आराम तो मिलता है, लेकिन आयुर्वेद इसे जड़ से ठीक करने का मार्ग दिखाता है। पंचकर्म, योग, औषधीय तेल और सही आहार ,ये सब मिलकर न सिर्फ दर्द को दूर करते हैं, बल्कि शरीर को स्वस्थ और संतुलित भी बनाते हैं।

संत रवि साहब जी का आध्यात्मिक जीवन और शिक्षाएँ

संत रवि साहब जी गुजरात के निर्गुण संत-साहित्य के एक चमकते सितारे हैं। उनकी वाणी में भक्ति, योग, तपस्या और निर्गुण राम के प्रति गहरी आस्था का ऐसा समन्वय है, जो हर भक्त के हृदय को छू लेता है। उनकी शिक्षाएँ आज भी लोगों को सत्य, प्रेम और शांति की राह दिखाती हैं। उनके जीवन और रचनाओं में आध्यात्मिकता का ऐसा प्रकाश है, जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के करीब ले जाता है। आइए, उनके जीवन, साधना और शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानें।

प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक जागृति

संत रवि साहब जी का जन्म संवत् 1783 में गुजरात के आमोद मंडल के तणछा गाँव में हुआ था। वे वैश्य-श्रीमाली जाति से थे। उनके पिता मनछा राम और माता इच्छा-बाई दोनों ही सात्विक और धर्मपरायण थे। माता-पिता की पवित्रता और साधु-संतों की संगति ने रवि साहब के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन से ही उनका मन भक्ति और अध्यात्म की ओर झुका हुआ था। वे साधु-संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। धीरे-धीरे उनके हृदय में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ और वे एक सच्चे सद्गुरु की तलाश में निकल पड़े।

उस समय गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में संत भाण साहब जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता था। लोग उन्हें संत कबीर और दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। उनकी वाणी में परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का ऐसा चित्रण था, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। रवि साहब उनकी साधना और शिक्षाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भाण साहब को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया।

गुरु भाण साहब की शरण और आत्म-साक्षात्कार

संत रवि साहब ने भाण साहब जी के चरणों में शरण ली। गुरु ने उन्हें उपदेश दिया कि संसार का सारा आश्रय मिथ्या है, केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। उनके मार्गदर्शन में रवि साहब ने परम ज्योति का साक्षात्कार किया। गुरु की कृपा से उनके सामने माया और अविद्या का पर्दा हट गया। वे सच्चिदानंद के रस में डूब गए और संसार के मोह-माया को त्यागकर साधना, भजन और तप में लीन हो गए।

उनके हृदय में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी। गुरु का एक पल का वियोग भी उनके लिए असहनीय था। एक बार भाण साहब ने उन्हें साधना का गूढ़ रहस्य बताया और शेडखी में रहने का आदेश देकर स्वयं कमिजडा के लिए प्रस्थान कर गए। रवि साहब को अपने साथ न ले जाने का निर्णय भाण साहब ने इसलिए लिया, क्योंकि वे जानते थे कि रवि साहब उनके वियोग का दुख सहन नहीं कर पाएँगे। कमिजडा में भाण साहब ने जीवित समाधि ले ली। यह समाचार सुनकर रवि साहब का हृदय विरह से भर गया। वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन गुरु के उपदेशों को याद कर उन्होंने प्राणियों को आध्यात्मिक चेतना देने का संकल्प लिया।

भक्ति और प्रचार का संकल्प

गुरु भाण साहब के ब्रह्मलीन होने के बाद संत रवि साहब ने गाँव-गाँव घूमकर भगवद् भक्ति का प्रचार शुरू किया। भाण साहब लोहाणा जाति से थे, इसलिए इस समुदाय में उनकी गहरी निष्ठा थी। सात हजार लोहाणों ने रवि साहब की शरण ली और उनके उपदेशों से अपना जीवन धन्य किया। रवि साहब ने अपने गुरु के पुत्र खीम साहब को भी शिष्य बनाया और उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया। खीम साहब को उन्होंने सायर के समुद्र तट पर रहने का आदेश दिया। खीम साहब भी एक सिद्ध संत बने।

रवि साहब ने सूरत, शेडखी और अन्य स्थानों पर सत्संग के माध्यम से लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनके सत्संग में खिंचे चले आते थे। शेडखी में रहते हुए उन्होंने अपनी अमर रचना विमल सत वाणी की रचना शुरू की।

भक्त कवि प्रीतमदास और अन्य संतों से भेंट

अपने भ्रमण के दौरान रवि साहब की मुलाकात गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि प्रीतमदास से हुई। लखारा गाँव में प्रीतमदास ने उनका स्वागत किया और दोनों ने कुछ दिन साथ बिताए। यह मिलन गंगा-यमुना के संगम की तरह पवित्र था। दोनों ने एक-दूसरे के सत्संग का रसपान किया। इसके बाद रवि साहब गिरनार पर्वत पर तप करने गए, जहाँ उन्हें दत्तात्रेय और योगसिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन हुए। कच्छ में उनकी भेंट प्रसिद्ध संत निर्भय राम से हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने खीम साहब के पुत्र गगा साहब को अपना शिष्य बनाया।

रवि साहब की रचनाएँ और शिक्षाएँ

संत रवि साहब की रचनाएँ भक्ति और ज्ञान का अनमोल खजाना हैं। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं:

ग्रन्थ चिंतामणिः यह रचना उनके गहरे आध्यात्मिक चिंतन और भक्ति के भाव को दर्शाती है। इसमें परमात्मा के निर्गुण और सगुण स्वरूप का सुंदर समन्वय है।

विमल सत वाणीः यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें भगवान के नाम की महिमा और साधना का सार बताया गया है। इस रचना को उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान पूर्ण किया।

पद और भजनः उनके अनेक भजन और पद गुजराती संत-साहित्य में आज भी गाए जाते हैं। इनमें भक्ति, वैराग्य और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव झलकता है।

उनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र था—राम नाम की साधना। वे कहते थे कि सारी साधनाएँ छोड़कर केवल राम नाम का जाप करना चाहिए। राम नाम ही संसार का सार है। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है:

रग-रग राम रमि रह्यो, निरगुन अगुन के रूप।
राम श्याम रवि एक ही, सुदर सगुन सरूप।।

इसमें उन्होंने राम के निर्गुण और सगुण रूपों का समन्वय किया। वे कहते थे कि जीभ से राम नाम का उच्चारण, कान से उसका श्रवण और नयनों से राम का दर्शन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। यही लोक और आत्मा का कल्याण करता है।

उन्होंने सिखाया कि मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता। बिना हरि भजन के यह जीवन व्यर्थ है। संसार के नश्वर बंधनों में फँसने की बजाय, भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। उनकी वाणी में सादगी और गहराई का अनोखा संगम था, जो हर श्रोता के हृदय को छू लेता था।

शिष्य और आध्यात्मिक विरासत

संत रवि साहब के असंख्य शिष्य थे, जिनमें खीम साहब, गगा साहब, कादर साहब और मुरार साहब विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। मुरार साहब मारवाड़ के थराड राज्य के राजकुमार थे। उन्होंने शेडखी में रवि साहब से दीक्षा ली और उनके आदेश पर जामनगर के खम्भालिया गाँव में मंदिर बनाकर भगवान का भजन शुरू किया।

रवि साहब ने मुरार साहब को वचन दिया था कि वे अपने जीवन का अंत खम्भालिया में ही करेंगे। संवत् 1860 में वांकानेर में उनके प्राण निकल गए, लेकिन गुरु का वचन निभाने के लिए एक चमत्कार हुआ। मुरार साहब उनकी देह को पालकी में खम्भालिया ले जा रहे थे। रास्ते में पालकी से आवाज आई, "मुरार, धीरे-धीरे ले चलो।" मुरार साहब ने देखा तो रवि साहब ने करवट बदली थी। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। खम्भालिया पहुँचकर रवि साहब ने समाधि ली और अपने वचन को पूर्ण किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और योगदान

संत रवि साहब का जीवनकाल भारत के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दौर से गुजरा। उस समय दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी। पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड की व्यापारिक कंपनियाँ भारत में अपने पैर जमा रही थीं। मध्य भारत में मराठा शक्ति अपने चरम पर थी, और राजस्थान अपनी स्वतंत्रता के लिए अडिग था। ऐसे समय में रवि साहब ने सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं ने गुजराती समाज में आध्यात्मिक क्रांति लाई। उन्होंने अपने गुरु भाण साहब के तत्वज्ञान को 'नाद' शाखा के रूप में आगे बढ़ाया, जबकि खीम साहब ने 'वुन्द' शाखा को संरक्षित किया।

संत रवि साहब जी का जीवन भक्ति, तप और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। उनकी रचनाएँ और शिक्षाएँ आज भी हमें प्रेरित करती हैं। राम नाम की साधना को उन्होंने जीवन का मूल मंत्र बताया। उनकी वाणी में सत्य और प्रेम का ऐसा प्रकाश है, जो हमें अंधेरे से निकालकर परमात्मा की ओर ले जाता है। वे न केवल एक संत थे, बल्कि एक सिद्ध योगी और समाज सुधारक भी थे। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल भगवान के नाम में ही है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

मोहन भागवत का 75 साल वाला बयान क्यों हो रही है बहस?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत जी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें कही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके 75 साल वाले बयान को लेकर हो रही है। यह बयान जुलाई 2025 में एक किताब के लॉन्च के दौरान आया था। उस समय भागवत जी ने मोरोपंत पिंगले, जो आरएसएस के पुराने विचारक थे, उनकी बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पिंगले जी को 75 साल की उम्र में सम्मानित किया गया था और उन्होंने मजाक में कहा था कि यह रिटायरमेंट का संकेत है। इस बयान को कई लोगों ने ऐसा समझा कि भागवत जी कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए।

यह बात इसलिए और गर्म हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। भागवत जी खुद भी जल्द ही 75 साल के होने वाले हैं। विपक्षी पार्टियों ने इसे मौका बनाकर सवाल उठाया कि क्या मोदी जी रिटायर होंगे? कुछ लोगों ने इसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच मतभेद का संकेत माना। लेकिन 28 अगस्त 2025 को दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागवत जी ने साफ किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि 75 साल पर रिटायर होना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल पर रिटायर होना चाहिए। संघ मुझे जो काम देगा, मैं करूंगा, चाहे 80 साल की उम्र हो।"

यह बहस क्यों हो रही है? एक तरफ बीजेपी कहती है कि उनकी पार्टी में 75 साल का कोई नियम नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बीजेपी के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। लेकिन पुराने उदाहरण देखें तो लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को 75 साल की उम्र में साइडलाइन किया गया था। दूसरी तरफ, कुछ लोग कहते हैं कि यह अनौपचारिक नियम है, पर अपवाद भी हैं। जैसे, 80 साल के जीतन राम मांझी अभी सरकार में हैं। बहस का एक पहलू यह भी है कि क्या आरएसएस बीजेपी पर दबाव डाल रही है? भागवत जी ने साफ किया कि आरएसएस सिर्फ सलाह देती है, फैसले बीजेपी खुद लेती है। फिर भी, दोनों के बीच गहरे संबंध होने से राजनीति में सवाल उठते हैं।

क्या यह बयान मोदी जी के लिए संकेत था या सिर्फ मजाक? यह सोचने वाली बात है। एक तरफ यह नेतृत्व में नई पीढ़ी लाने का विचार लगता है, दूसरी तरफ पुराने नेताओं के अनुभव की कीमत भी है। समाज को यह विचार करना चाहिए कि उम्र से ज्यादा कामकाज महत्वपूर्ण है या नहीं। यह बहस सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। आम लोग भी सोचते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि 75 साल पर आराम करना अच्छा है, ताकि युवाओं को मौका मिले। लेकिन भागवत जी का स्पष्टीकरण बताता है कि बातों को गलत समझा जा सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिससे बहस और तेज हुई। क्या हमें बयानों को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए? हां, क्योंकि आधी-अधूरी बातें गलतफहमी पैदा करती हैं। यह बयान हमें सिखाता है कि किसी भी बात को समझने से पहले उसका पूरा सच जानना जरूरी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गईं अहम बातें

28 अगस्त 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक लेक्चर सीरीज हुई। वहां मोहन भागवत जी ने करीब ढाई घंटे तक सवालों के जवाब दिए। उन्होंने 200 से ज्यादा सवालों का सामना किया। एक महत्वपूर्ण बात थी आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते के बारे में। भागवत जी ने कहा कि दोनों में कोई मतभेद नहीं है। आरएसएस सिर्फ सलाह देती है, लेकिन बीजेपी अपने फैसले खुद लेती है। उन्होंने बीजेपी के नए अध्यक्ष चुनने में देरी पर मजाक में कहा कि अगर आरएसएस फैसला लेती तो इतना समय नहीं लगता। लेकिन फिर साफ किया कि यह बीजेपी का अपना मामला है।

भागवत जी ने इस्लाम पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लाम की हमेशा जगह रहेगी। धर्म व्यक्तिगत मामला है और जबरदस्ती या लालच से धर्म बदलना गलत है। उन्होंने अवैध प्रवासन और जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई। कहा कि भारतीय नागरिकों को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वे मुस्लिम हों या कोई और। क्या यह बातें समाज में सद्भाव बढ़ाएंगी? कुछ लोग इसे समावेशी मानते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि यह हिंदू-मुस्लिम विभाजन को छुपाने की कोशिश है। यह विचार करने की बात है कि क्या धार्मिक एकता के लिए ऐसी बातें काफी हैं।

भाषा के मुद्दे पर भी उन्होंने बोला। कहा कि मातृभाषा और राज्य की भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन लेन-देन के लिए एक ऐसी भाषा जरूरी है जो विदेशी न हो। अंग्रेजी सीखना ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय हैं। यह विचार अच्छा है, लेकिन क्या इससे भाषाई विवाद बढ़ेंगे? उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर पहले भी बहस हो चुकी है। भागवत जी कहते हैं कि सहमति से भाषा चुनें, जो सोचने लायक बात है।

हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्होंने कहा कि इसे घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह पहले से है। संतों ने इसे घोषित किया है। इसे स्वीकार करने से फायदा होगा, नकारने से नुकसान। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? कुछ लोग कहते हैं हां, क्योंकि यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं। लेकिन संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह बहस गहरी और विचारोत्तेजक है। भागवत जी ने धर्म परिवर्तन पर भी कहा कि यह जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता मजबूत होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागवत जी ने आरएसएस को आधुनिक और सहिष्णु दिखाने की कोशिश की। लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि यह सिर्फ छवि सुधारने का प्रयास है। क्या आरएसएस बदल रही है? 100 साल में यह संगठन बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन चुनौतियां भी सामने हैं।

जाति व्यवस्था पर क्या बोले भागवत जी?

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे पुरानी और जटिल समस्या है। मोहन भागवत जी ने कई बार इस पर अपनी राय रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था पहले थी, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। जो पुरानी चीजें हैं, वे धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जाति में श्रेष्ठता का भ्रम छोड़ देना चाहिए। सभी लोग बराबर हैं। उन्होंने 1972 के उदुपी घोषणा का जिक्र किया, जहां धार्मिक नेताओं ने कहा था कि शास्त्रों में अस्पृश्यता या जन्म से भेदभाव का कोई आधार नहीं है। यह गलत व्याख्या का नतीजा है।

भागवत जी ने कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें कठोरता है। आरक्षण के बारे में उन्होंने समर्थन जताया। कहा कि अगर 1000 साल तक जातिगत भेदभाव सहा गया है, तो 200 साल तक आरक्षण सहना धर्म है। आरक्षण तब तक चलना चाहिए जब तक जरूरत हो और लाभ लेने वाले खुद कहें कि अब इसकी जरूरत नहीं। क्या यह विचार समाज को एकजुट करेगा? एक तरफ दलित और पिछड़े वर्ग खुश हैं, क्योंकि आरक्षण का समर्थन है। लेकिन कुछ ऊपरी जातियां कहती हैं कि इससे मेरिट प्रभावित होता है। बहस यह भी है कि आरक्षण जाति आधारित हो या आर्थिक आधार पर।

पहले भी भागवत जी ने कहा था कि पंडितों ने गलत तरीके से जाति व्यवस्था बनाई। सभी लोग भगवान के सामने बराबर हैं। वर्ण और जाति को भूल जाना चाहिए, यह पुरानी बात है। अप्रैल 2025 में उन्होंने कहा कि एक कुआं, एक मंदिर, एक श्मशान से जाति भेद मिटेगा। क्या आरएसएस इस दिशा में काम कर रही है? शाखाएं सभी के लिए खुली हैं, लेकिन क्या व्यावहारिक रूप से बदलाव दिख रहा है? कुछ लोग कहते हैं हां, कुछ कहते हैं कि अभी बहुत काम बाकी है। जाति व्यवस्था समाज को तोड़ती है। भागवत जी का कहना है कि एकजुट हिंदू समाज जरूरी है। लेकिन क्या बिना जाति मिटाए यह संभव है? हमें सोचना चाहिए कि शिक्षा और जागरूकता से कैसे बदलाव लाया जाए। यह विचार करने की बात है कि पुरानी परंपराओं को कब और कैसे छोड़ें।

काशी-मथुरा आंदोलन और अखंड भारत पर विचार

काशी और मथुरा का विवाद लंबे समय से चल रहा है। भागवत जी ने कहा कि आरएसएस राम मंदिर आंदोलन के बाद काशी-मथुरा के लिए आधिकारिक रूप से नहीं जुड़ेगी। लेकिन अगर हिंदू समाज मांगे, तो स्वयंसेवक व्यक्तिगत रूप से मदद कर सकते हैं। इन जगहों का हिंदुओं के लिए सांस्कृतिक महत्व है। अगर ये हिंदू पक्ष को सौंप दी जाएं, तो भाईचारा बढ़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अगर काशी-मथुरा पहले मिल गए होते, तो आज की नाराजगी नहीं होती। लेकिन भागवत जी ने यह भी कहा कि नए विवाद पैदा न करें, ताकि समाज में विभाजन न हो।

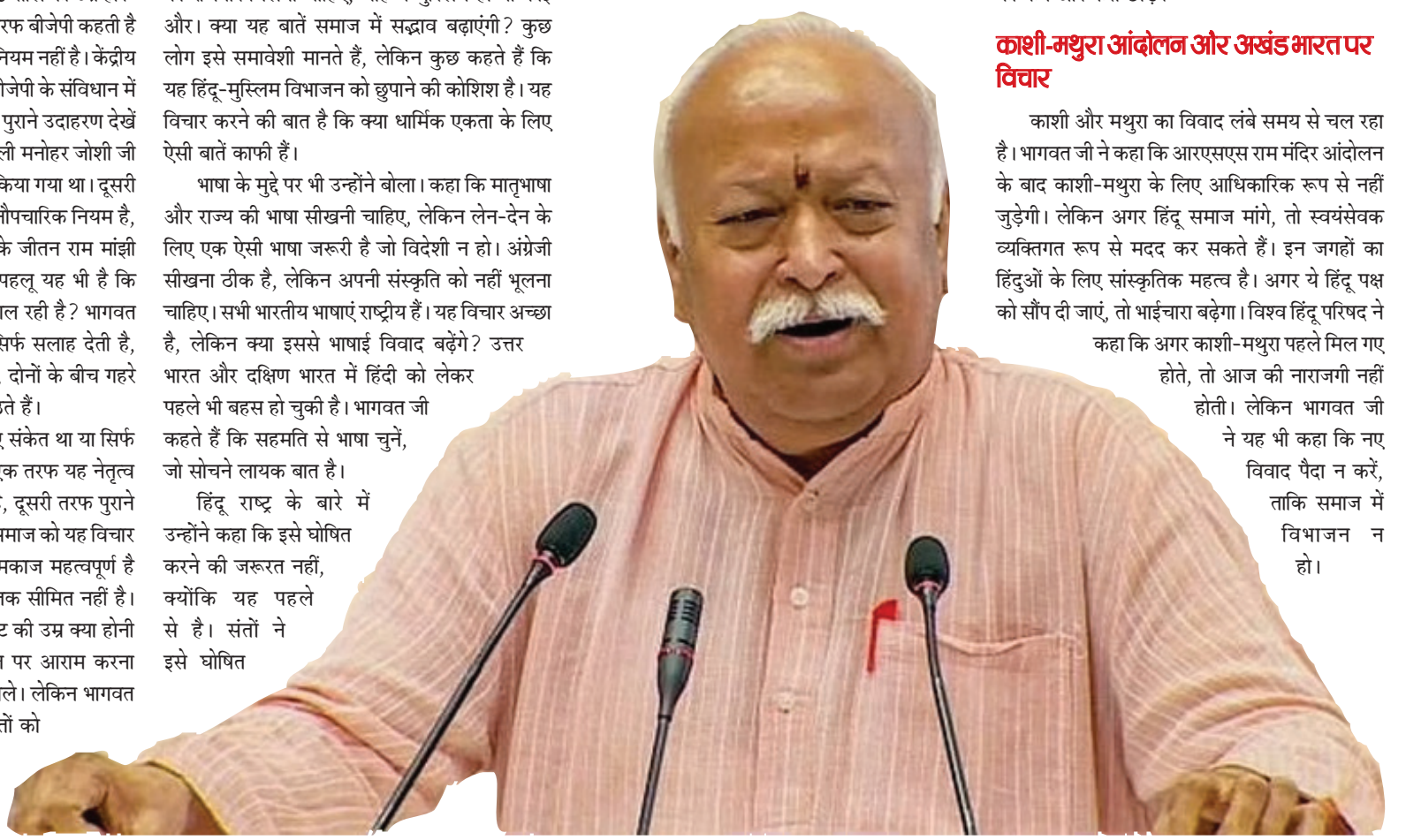

अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है

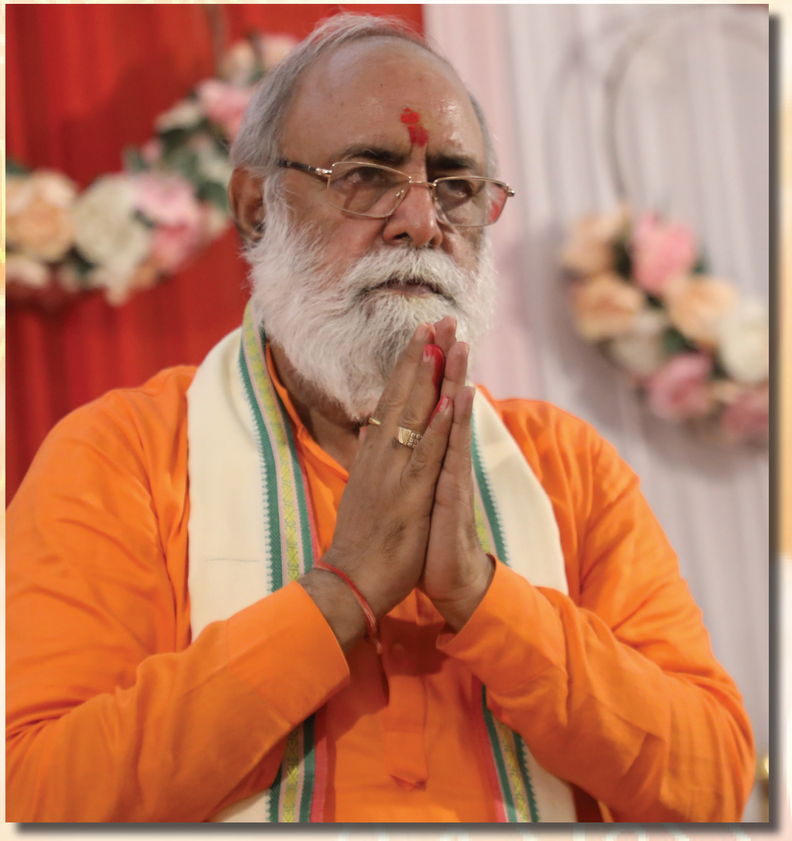

मनुष्य में जब अहंकार आ जाता है तो उसका पतन हो जाता है। कई बार सेवादार में भी अकड़ आ जाती है जो उसके लिए अनिकारक होती है। किसी को कुछ धन प्राप्त हो गया, संतान की प्राप्ति हो गई, कोई पद मिल गया या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गया तो उसमें यदि अकड़ आ जाए तो वह उसको पतन की ओर ले जाती है। जैसा कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप को ही ले लो, उनमें अहंकार चरम सीमा पर है। वे करने को तो हमारे मित्र हैं लेकिन उन्होंने जिस तरह से टैरिफ लगाया है वह भारत के हित में नहीं है। क्या ये हमारे मित्र हैं? ये हमारे मित्र नहीं, शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही शालीनता के साथ कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कौन बनाएगा? मां दुर्गा बनाएगी। मैं तो यह कहता हूं कि तीसरी नहीं, भारत पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम स्वदेशी को अपनाएं। यदि ऐसा हो जाए तो हमारा आयात घट जाएगा तथा विदेशी मुद्रा का भंडार निर्यात के बढ़ जाने से बढ़ जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर उन्नति करेगी। उदाहरण के तौर पर केवल दवाइयों के निर्यात पर ही भारत का निर्यात 40 करोड़ अरब विदेशी मुद्रा का भंडार व्यय होता है।यदि हम अपने देश में ही ये दवाइयां बनाने लग जाएं तो इससे इतना बड़ा निवेश बच जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था में उन्नति होगी।

जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण के अवतार हैं पूज्य जगद्गुरु

भगवान श्रीकृष्ण जगद्गुरु हैं और पूज्य स्वामी जी को जगद्गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने संपूर्ण विश्व में मानवता व जन सामान्य का कल्याण कार्य किया है। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज सचमुच साक्षात जगद्गुरु के अवतार हैं। जगत का गुरु वही हो सकता है जिसके मन में जगत के कल्याण की भावना हो। पूज्य स्वामी के पास अपने लिए कुछ नहीं है। इनका समग्र जीवन जनता व संसार के लिए है। इसलिए सच्चे अर्थों में ये जगद्गुरु के रूप हैं। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वचनों का उपदेशों व संदेशों का श्रवण करने को मिला है। इन्होंने इतना दुर्लभग्रंथ मयखाना की रचना की है जिसमें न्याय, दर्शन और शास्त्र निहित हैं। निश्चित रूप से हमें इसका परायण करना चाहिए, स्वाध्याय और अध्ययन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा।

(प्रो. शिव शंकर मिश्र जी,
कुलपति, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन)

महाग्रंथ मयखाना में है वेदों, उपनिषदों व शास्त्रों का निचोड़

कल सभी काशी विद्वत परिषद के विद्वानों द्वारा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का अभिनंदन वंदन किया गया। जिसमें काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री व अन्य सम्मानित सदस्यगण भी उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में हस्ताक्षर करके परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का अभिनंदन किया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हमारे बीच में भगवान के रूप में सुशोभित हैं। ये ऋषि व मुनि के रूप में विद्यमान हैं जो हम सभी के कष्ट व दुखों का निवारण कर रहे हैं और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हम कामना करते हैं कि ये दीर्घायु हों। सद्गुरुदेव जी ने 12 वर्ष की आयु में मयखाना की रचना की। यह ऐसा ग्रंथ है कि न भूतो न भविष्यति। विद्वान लोग इसका चिंतन करेंगे तो उसमें सब वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों व दर्शन का निचोड़ उनको मिल जाएगा। मैं इन्हें नमन करता हूं।

(डा. दिनेश कुमार गर्ग जी ,कोषाध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता काशी विद्वत परिषद, काशी)

संसार के जीवों का कल्याण कर रहे हैं जगद्गुरु

यह अद्भुत काल है कि जिसमें महाराज जी के द्वारा अपने अर्जित मंत्रों की शक्ति के माध्यम से समस्त संसार के जीवों का कल्याण हो रहा है। आप अपनी मंत्र साधना के द्वारा असाध्य रोगों का निवारण करके मानव के दुखों का निवारण कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव जी भगवान के विषय में हमारे शास्त्रों में चर्चा की गई है कि गुरु तत्व पर जो विश्वास रखते हैं, उनकी सारी क्रियाएं यथार्थ होने लगती हैं। पूज्य महाराज जी ने 12 वर्ष की अल्पायु जिसमें अक्षर ज्ञान भी नहीं होता, परमात्मा की कृपा से एक अद्भुत ज्ञान की राशि को संग्रहित कर दिया है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेदांती, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत तथा शुद्धाद्वैत का दर्शन करते हैं। महाराजश्री ने अपनी प्रतिभा व पुण्यों के द्वारा, साधना, तप, स्वाध्याय के द्वारा जो लेखन किया है वह आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। इनकी उपासना और आराधना को देखकर काशी विद्वत परिषद ने इनका अभिनंदन और वंदन किया है। ईश्वर इनको ऊर्जा व शक्ति दे जिसके माध्यम से समाज का कल्याण हो तथा सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार हो।

(प्रो. राम नारायण द्विवेदी
महामंत्री, काशी विद्वत परिषद, काशी)

पूरे विश्व ने माना मंत्रों से होता है जीवन में परिवर्तन

निरंजनी अखाड़े ने जो महाराज श्री को जो पद दिया है, अब तक के इतिहास में किसी भी अखाड़े ने यह जगद्गुरु की उपाधि नहीं दी है। महाराजश्री पहले हैं, जिन्हें जगद्गुरु की उपाधि मिली है। जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह जगद्गुरु की उपाधि क्यों और कैसे मिली है। महाराजश्री कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये इस युग में ईश्वर के रूप में अवतरित हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी निष्ठा, विश्वास और भक्ति आपके जीवन को बदल देगी। गुरु का मंत्र जब आपको मिलेगा तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। जब निष्ठा, भक्ति और निसंदेह आपके मन में होगा तब मेरे ठाकुर आपके पास होंगे। पूरे विश्व ने इन गुरु के मंत्रों की ताकत को देखा है। पूरे विश्व ने यह भी माना है कि मंत्रों से जीवन में मंत्रों से परिवर्तन होता है। कितने असाध्य किडनी, लीवर आदि ठीक कर दिए। मैंने अखबार में पढ़ा है कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज के जीवन में भी परिवर्तन हुआ, उनको भी स्वास्थ्य लाभ हुआ। आप अपनी निष्ठा, विश्वास और भक्ति को बनाए रखें, यह आपके जीवन में परिवर्तन कर देगी। गुरु विश्वास है अतः विश्वास को बनाए रखें।

(महामंडलेश्वर स्वामी नवल गिरि जी महाराज)

एक बड़ा फैसला: गुजरात में बिटकॉइन अपहरण मामले में सजा

आज की दुनिया में बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्रा बहुत चर्चा में है। लेकिन कभी-कभी यह अच्छी चीजें लाने की बजाय मुसीबतें पैदा कर देती है। गुजरात में एक पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। 29 अगस्त 2025 को अहमदाबाद की एक अदालत ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें पूर्व भाजपा विधायक नलिन कोटडिया, पूर्व आईपीएस अधिकारी जगदीश पटेल और कई पुलिस वाले शामिल हैं। यह मामला 2018 का है, जब इन लोगों ने सूरत के एक बिल्डर शैलेश भट्ट का अपहरण किया और उनसे 12 करोड़ रुपये के बिटकॉइन जबरन ट्रांसफर करवाए।

यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पुलिस और राजनीति के लोग शामिल हैं। लोग सोचते हैं कि कानून रखवाले खुद कानून तोड़ दें तो क्या होगा? इस लेख में हम इस पूरी कहानी को सरल भाषा में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी निवेश की गलती बड़ी अपराध की जड़ बन गई। कहानी में कई मोड़ हैं, जहां हर कोई गलत काम करता नजर आता है। लेकिन अदालत ने अपना काम किया और सजा दी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पैसा और ताकत का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है।

शुरुआत से देखें तो यह मामला सिर्फ एक अपहरण नहीं है। इसमें कई परतें हैं। शैलेश भट्ट खुद भी पूरी तरह निर्दोष नहीं थे। उन्होंने पहले दूसरों से बिटकॉइन ऐंठे थे। फिर उन पर हमला हुआ। पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी भूलकर लालच में आ गए। विधायक जैसे नेता भी इसमें फंस गए। यह पूरी घटना गुजरात की राजनीति और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जांच हुई और न्याय मिला। अब आगे विस्तार से जानते हैं।

कहानी की शुरुआत: बिटकॉइन की चमक और धोखे की छाया

बिटकॉइन क्या है? यह एक तरह की डिजिटल मुद्रा है जो इंटरनेट पर चलती है। लोग इसमें निवेश करते हैं ताकि पैसा बढ़े। लेकिन 2016-2017 में भारत में नोटबंदी के बाद कई लोग काले धन को सफेद करने के लिए बिटकॉइन की ओर मुड़े। गुजरात के सूरत में एक कंपनी थी बिटकनेक्ट। इसका मालिक सतीश कुंभानी था। यह कंपनी निवेशकों को बड़ा मुनाफा देने का वादा करती थी। शैलेश भट्ट ने इसमें 1 करोड़ रुपये से ज्यादा लगाए। लेकिन कंपनी एक घोटाला निकली। कुंभानी भाग गया और निवेशकों का पैसा डूब गया।

शैलेश भट्ट गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि अपना पैसा वापस लेंगे। फरवरी 2018 से पहले, उन्होंने कुंभानी के दो कर्मचारियों को अगवा किया। इनमें धवल मावानी और अन्य थे। भट्ट और उनके साथियों ने खुद को आयकर अधिकारी बताकर उन्हें पकड़ा। फिर मारपीट करके 2091 बिटकॉइन, 11000 लाइटकॉइन और 14.5 करोड़ रुपये

नकद ऐंठ लिए। उस समय इन बिटकॉइन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपये थी। भट्ट ने इनमें से कुछ बिटकॉइन अपने साथी किरीट पलाडिया को दिए।

यह काम भट्ट ने गुस्से में किया, लेकिन यह गैरकानूनी था। बाद में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भट्ट को 2024 में गिरफ्तार किया। उन्हें मनी लॉन्डरिंग के आरोप में जेल हुई। लेकिन उस समय, 2018 में, भट्ट के पास ये बिटकॉइन थे। अब कहानी में नया मोड़ आया। कुछ लोगों को पता चला कि भट्ट के पास इतने बिटकॉइन हैं। इनमें अमरेली पुलिस के अधिकारी और पूर्व विधायक नलिन कोटडिया शामिल थे।

कोटडिया धारी सीट से 2012-2017 तक विधायक थे। वे भाजपा में थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। जगदीश पटेल अमरेली के एसपी थे। अनंत पटेल पुलिस इंस्पेक्टर थे। इनके अलावा सीबीआई इंस्पेक्टर सुनील नायर, वकील केतन पटेल और कई कांस्टेबल थे। इन्होंने सोचा कि भट्ट से बिटकॉइन ऐंठ सकते हैं। उन्होंने साजिश रची। यह दिखाता है कि कैसे लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। पुलिस वाले जो कानून की रक्षा करते हैं, वे खुद अपराधी बन गए।

अपहरण की घटना: ताकत का गलत इस्तेमाल

9 फरवरी 2018 को घटना हुई। शैलेश भट्ट और उनका साथी किरीट पलाडिया गांधीनगर में एक पेट्रोल पंप पर थे। अचानक अमरेली पुलिस की टीम आई। वे सरकारी गाड़ियों में थे। अनंत पटेल की अगुवाई में उन्होंने भट्ट और पलाडिया को पकड़ा। उन्हें डराया कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन असल में यह अपहरण था।

उन्हें एक फार्महाउस पर ले गए। वहां मारपीट की। भट्ट को कहा कि तुम्हारे पास बिटकॉइन हैं, ट्रांसफर करो। भट्ट डर गए। उन्होंने 200 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दिए। उस समय इनकी कीमत 12 करोड़ रुपये थी। साथ ही 32 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई। कुछ स्रोतों में 9 करोड़ भी कहा गया, लेकिन मुख्य रूप से 12 करोड़ के बिटकॉइन थे। सुनील नायर ने 5 करोड़ रुपये नकद लिए।

यह सब पुलिस की वर्दी में हुआ। कांस्टेबल 9 थे। वे सब मिले हुए थे। नलिन कोटडिया ने साजिश में मदद की। जगदीश पटेल ने ऊपर से सपोर्ट दिया। भट्ट को छोड़ा गया, लेकिन वे डरे हुए थे। बाद में उन्होंने शिकायत की। यह घटना दिखाती है कि कैसे ताकतवर लोग कमजोर को दबाते हैं। भट्ट खुद अपराधी थे, लेकिन पुलिस का काम न्याय देना है, न कि लूटना।

इस अपहरण से गुजरात में हड़कंप मच गया। लोग सोचने लगे कि पुलिस पर भरोसा कैसे करें? राजनीति में ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि भट्ट की अपनी गलतियां थीं। उन्होंने पहले दूसरों को सताया, फिर खुद सताए गए। यह एक चेन रिएक्शन जैसा था। बिटकॉइन की चमक ने सबको अंधा कर दिया।

जांच और अदालत की कार्रवाई: लंबा सफर न्याय का

शैलेश भट्ट ने शिकायत की तो गुजरात सरकार के गृह विभाग ने CID क्राइम को जांच सौंपी। FIR दर्ज हुई। अपहरण, जबरन वसूली और साजिश के आरोप लगे। IPC की कई धाराएं लगीं।

जांच में 15 लोग गिरफ्तार हुए। नलिन कोटडिया भागते रहे। सितंबर 2018 में महाराष्ट्र के जलगांव से पकड़े गए। जगदीश पटेल, अनंत पटेल और अन्य को भी गिरफ्तार किया। सबको जमानत मिली। लेकिन मुकदमा चला। अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट की ACB स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। जज बी.बी. जादव थे।

ट्रायल में गवाहियां हुईं। सबूत पेश किए गए। भट्ट ने अपनी कहानी बताई। पुलिस वालों के वकील ने कहा कि वे निर्दोष हैं, लेकिन अदालत ने नहीं माना। 29 अगस्त 2025 को फैसला आया। 15 में से 14 दोषी पाए गए। एक बिपिन पटेल या जतिन पटेल छूट गया। बाकी सबको उम्रकैद। इसमें कोटडिया, जगदीश पटेल, अनंत पटेल और 9 कांस्टेबल शामिल।

वकीलों ने कहा कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल सजा हो गई। यह जांच 7 साल चली। इससे पता चलता है कि न्याय प्रक्रिया धीमी है, लेकिन होती है। बीच में भट्ट खुद ED के चंगुल में फंसे। 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका केस अलग है। लेकिन इस मामले में वे शिकायतकर्ता थे।

यह फैसला संतुलित है। क्योंकि दोनों तरफ गलतियां थीं। लेकिन अदालत ने पुलिस की जिम्मेदारी पर जोर दिया। वे जनता की सेवा के लिए हैं, न कि लूट के लिए।

क्या सीख मिलती है: समाज और कानून पर विचार

यह पूरा मामला हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। पहला, बिटकॉइन जैसी नई तकनीक अच्छी है, लेकिन इसमें खतरे भी हैं। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। नोटबंदी के बाद गुजरात में बिटकॉइन का चलन बढ़ा, लेकिन घोटाले भी हुए।

दूसरा, पुलिस और नेताओं की मिलीभगत खतरनाक है। जगदीश पटेल जैसे आईपीएस अधिकारी अगर गलत करें तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। नलिन कोटडिया जैसे विधायक अगर पैसों के लिए अपराध करें तो जनता का भरोसा टूटता है। लेकिन अच्छी बात है कि जांच हुई और सजा मिली। यह दिखाता है कि कानून सबके लिए बराबर है।

तीसरा, शैलेश भट्ट की कहानी से सीख मिलती है कि गलत काम का बदला गलत काम से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने पहले अपहरण किया, फिर खुद शिकार बने। यह एक सर्कल जैसा है। समाज में अगर हर कोई बदला लेने लगे तो अराजकता फैल जाएगी।

चौथा, क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार को और सख्त नियम बनाने चाहिए। ED जैसी एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन और जागरूकता जरूरी है। लोग निवेश करें, लेकिन सावधानी से।

यह मामला विचारोत्तेजक है। क्या हमारी व्यवस्था में अभी भी भ्रष्टाचार है? क्या पुलिस सुधार की जरूरत है? क्या राजनीति पैसों से चलती है? ये सवाल हैं जो हमें सोचने चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि ऐसे फैसले से सुधार आएगा। न्याय हुआ, यही बड़ी बात है। यह कहानी लंबी है, लेकिन सरल। इसमें इंसानी कमजोरियां दिखती हैं। लालच, ताकत का दुरुपयोग, बदला। लेकिन अंत में कानून जीता। गुजरात ही नहीं, पूरे देश के लिए यह उदाहरण है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

संभल की हिंसा और रिपोर्ट: एक नजर

संभल उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। यहां नवंबर 2024 में काफी हिंसा हुई थी। एक मस्जिद की जांच के दौरान लोग भिड़ गए। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। चार लोग मारे गए और कई घायल हो गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमिटी बनाई। उस कमिटी ने अब अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। जैसे, हिंदुओं की आबादी कम होना। पहले 45% थे, अब 15% रह गए। रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है।

संभल में क्या हुआ: हिंसा की शुरुआत

संभल में नवंबर 2024 की 24 तारीख को हिंसा भड़क गई। वजह थी शाही जामा मस्जिद की जांच। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पहले हरिहर मंदिर था। कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। जांच करने वाली टीम मस्जिद पहुंची। वहां लोग इकट्ठा हो गए। पत्थरबाजी हुई। गाड़ियां जलाई गईं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। गोली चली। चार लोग मारे गए। ज्यादातर मुस्लिम थे। 29 पुलिसवाले घायल हुए।

सरकार ने जांच के लिए तीन लोगों की कमिटी बनाई। कमिटी के प्रमुख थे रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा। दूसरे थे पूर्व पुलिस अधिकारी अरविंद कुमार जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद। कमिटी ने 450 पेज की रिपोर्ट बनाई। यह रिपोर्ट 28 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन सूत्रों से कुछ बातें बाहर आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा एक साजिश थी। बाहर से लोग लाए गए थे। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की स्पीच को ट्रिगर बताया गया है। उन्होंने 22 नवंबर को मस्जिद में भाषण दिया था।

लेकिन दूसरी तरफ की बात भी सुनिए। कुछ संगठन कहते हैं कि पुलिस ने ज्यादा सख्ती की। जांच टीम के साथ हिंदुत्व वाले लोग थे। वे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इससे तनाव बढ़ा। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और करवान-ए-मोहब्बत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस ने गोली चलाई। राज्य की मिलीभगत थी। बुलडोजर से घर तोड़े गए। बेल नहीं दी गई। पोस्टर लगाए गए। इससे लोग डर गए।

यह हिंसा नई नहीं है। संभल में पहले भी कई बार दंगे हुए हैं। रिपोर्ट में इतिहास पर रोशनी डाली गई है। हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि यह सब क्यों हो रहा है। शहर में तुर्क और पठान समुदायों के बीच पुरानी रंजिश है। तुर्क विदेशी मुस्लिम कहलाते हैं। पठान हिंदू से मुस्लिम बने हैं। यह रंजिश हिंसा का कारण बनती है। सरकार कहती है कि पुलिस ने अच्छा काम किया। दंगा फैलने नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन विपक्ष कहता है कि रिपोर्ट लीक करके भाजपा ध्यान भटका रही है। रोजगार और किसानों के मुद्दों से।

यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या धार्मिक जगहों पर जांच से तनाव बढ़ता है? या पुरानी दुश्मनी है? दोनों तरफ के लोग पीड़ित हैं। हमें शांति की जरूरत है।

आबादी का बदलाव: 45% से 15% तक का सफर

रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात है आबादी में बदलाव। आजादी के समय, 1947 में, संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू 45% थे। मुस्लिम 55%। अब हिंदू 15-20% रह गए। मुस्लिम 85% हो गए। 2011 की जनगणना में भी यही ट्रेंड दिखा। तब हिंदू 22% थे। मुस्लिम 77%।

रिपोर्ट कहती है कि यह बदलाव दंगों से हुआ। हिंदू डरकर चले गए। राजनीतिक तुष्टिकरण से मुस्लिमों को फायदा मिला। एक हिंदू जाति को खास निशाना बनाया गया। वे पैसा उधार देते थे। दंगों में उन्हें मारकर पैसा नहीं लौटाया। इससे डर फैला। हिंदू शहर छोड़कर चले गए।

भाजपा कहती है कि यह साजिश है। 100 से ज्यादा जिलों में ऐसा हो रहा है। हिंदुओं का पलायन। नेहरू के समय से तुष्टिकरण चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। हम संतुष्टिकरण करेंगे। सबको योजनाओं का फायदा मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं।

लेकिन दूसरी तरफ की राय भी है। मौलाना शब्बुद्दीन रिजवी कहते हैं कि हिंदू डर से नहीं गए। बेहतर पढ़ाई और नौकरी के लिए गए। शहर छोटा है। मौके कम हैं। लोग दिल्ली या दूसरे शहर जाते हैं। कांग्रेस के अजय राय कहते हैं कि रिपोर्ट से पहले ही बातें लीक हो रही हैं। भाजपा समाज को बांटना चाहती है। असली मुद्दे छिपा रही है।

क्या यह बदलाव चिंताजनक है? हां, अगर दंगों से हुआ तो। लेकिन अगर आर्थिक कारणों से तो अलग बात। हमें आंकड़े देखने चाहिए। 1952 में कुछ लोग कहते हैं हिंदू 56% थे। लेकिन रिपोर्ट 1947 के आंकड़े देती है। हमें और रिसर्च की जरूरत है। शहर में अब मुस्लिम ज्यादा हैं। लेकिन सब शांतिपूर्ण रह सकते हैं। बदलाव स्वाभाविक है। लेकिन हिंसा से नहीं होना चाहिए।

यह हमें सोचने देता है। क्या जनसंख्या का संतुलन जरूरी है? या विविधता में ताकत है? दोनों तरफ सोचिए।

दंगों का पुराना इतिहास: 15 बार की कहानी

संभल में दंगे नए नहीं। रिपोर्ट में 15 दंगों का जिक्र है। 1947 से 2019 तक। साल थे: 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019। कुल 184 मौतें हुईं। ज्यादातर हिंदू मारे गए।

रिपोर्ट कहती है कि पहले सरकारों ने तुष्टिकरण किया। पुलिस ने मुस्लिम नेताओं को खुश किया। हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 1978 का दंगा बड़ा था। तब से हिंदुओं का मस्जिद में जाना बंद हो गया। डर फैल गया।

2024 की हिंसा में भी यही। बाहर से दंगाई लाए गए। हथियार इस्तेमाल हुए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के बने। एक गैंग लीडर शारिक सठा का नाम है। पाकिस्तान की एजेंसी से जुड़ा। नकली नोट चलाता था। हथियार सप्लाई करता था।

विपक्ष कहता है कि यह प्रोटेस्ट था। पुलिस ने गोली चलाई। पांच मुस्लिम मारे गए। कुछ नाबालिग थे। जांच टीम के साथ हिंदुत्व वाले थे। नारे लगा रहे थे। इससे भड़का। बुलडोजर चले। घर तोड़े। 80 गिरफ्तारियां। 12 FIR। 2750 अज्ञात पर केस। सिविल राइट्स ग्रुप्स कहते हैं कि राज्य ने दबाव डाला। बेल नहीं दी। पोस्टर लगाए। डराया। लेकिन सरकार कहती है कि पुलिस ने बचाया। हिंदुओं का नरसंहार रोका। यह इतिहास हमें बताता है कि पुरानी दुश्मनी है। तुर्क-पठान की। लेकिन अब राजनीति मिल गई। हमें शांति के रास्ते ढूंढने चाहिए। बातचीत से।

रिपोर्ट की और बातें: आतंक और मंदिर का सबूत

रिपोर्ट में दंगों और आबादी के अलावा और भी है। संभल को आतंक का केंद्र बताया। अल कायदा और हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे ग्रुप वहां सक्रिय। मौलाना असिम उर्फ सना-उल-हक का नाम है। अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। नशीले पदार्थों का गैंग है। अवैध हथियार। मंदिर का सबूत भी। हरिहर मंदिर के नीचे बाबर काल के निशान मिले। 68 तीर्थ स्थल थे। 19 पवित्र कुएं। कई पर अतिक्रमण। योगी सरकार ने सफाई शुरू की। 30 मई 2025 को नींव रखी। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा साजिश थी। रेडिकल ग्रुप्स ने की। हिंदुओं को निशाना। लेकिन पुलिस ने रोका। दूसरी तरफ, विपक्ष कहता है कि रिपोर्ट भाजपा की साजिश है। कम्युनल टेंशन बढ़ाने की। लीक करके। असली मुद्दे छिपाने की। मौलाना कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित हैं। कोई डर नहीं।

यह सब हमें बताता है कि समस्या गहरी है। आतंक, हथियार, इतिहास। लेकिन समाधान भी है। सरकार पॉलिसी बना सकती है। पलायन रोके। लोग वापस लाए। लेकिन सब तरफ की सुननी चाहिए।

यह सब कितना चिंताजनक: सोचने का समय

यह रिपोर्ट चिंताजनक है। हिंदुओं की आबादी कम होना। दंगे। आतंक। लेकिन कितना? देखिए। अगर दंगों से पलायन हुआ तो बहुत चिंता की बात। हिंदुओं के अधिकारों का हनन। लेकिन अगर आर्थिक कारण तो अलग। शहर छोटा है। नौकरियां कम। लोग बाहर जाते हैं।

भाजपा कहती है कि यह बड़ा खतरा। पूरे देश में ऐसा। नीतियां बनानी होंगी। योगी कहते हैं कि अब तुष्टिकरण नहीं। संतुष्टिकरण। सब बराबर। विपक्ष कहता है कि भाजपा डर फैला रही है। वोट के लिए। असली समस्या बेरोजगारी, किसान।

“चूहा हाथी पर मुक्का मार रहा है”

अमेरिका के भारत पर टैरिफ की कहानी

आज की दुनिया में व्यापार और राजनीति एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। यह फैसला 27 अगस्त 2025 को लागू हुआ। वजह? भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने इसे “चूहे का हाथी पर मुक्का मारने जैसा” बताया है। उन्होंने रूस टुडे के साथ बातचीत में कहा कि अमेरिका खुद को दुनिया का बड़ा भाई समझ रहा है, लेकिन यह कदम उसके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।

यह खबर सिर्फ दो देशों की नहीं है। इसमें ब्रिक्स देशों की भूमिका है, जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। वोल्फ कहते हैं कि अगर अमेरिका भारत को रोकता है, तो भारत अपने सामान ब्रिक्स के बाकी देशों को बेचेगा। इससे ब्रिक्स और मजबूत होगा। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का हिस्सा 35 प्रतिशत है, जबकि जी7 का सिर्फ 28 प्रतिशत।

यह टैरिफ पहले 25 प्रतिशत था, लेकिन ट्रंप ने इसे दोगुना कर दिया। भारत ने इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया। भारत कहता है कि वह सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से 17 अरब डॉलर बचाए। लेकिन अब यह टैरिफ भारत के 48 से 60 अरब डॉलर के निर्यात को प्रभावित करेगा। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह फैसला दोनों देशों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, और भारत नए बाजार ढूंढेगा।

क्या यह सिर्फ व्यापार का मामला है? या इससे दुनिया की ताकत का संतुलन बदल रहा है? आइए इस पर गहराई से सोचें। यह कहानी बताती है कि कैसे बड़े देश छोटे फैसलों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका की यह रणनीति काम करेगी? या इससे ब्रिक्स जैसे समूह और मजबूत हो जाएंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।

अमेरिका क्यों कर रहा है ऐसा? उसकी वजहें

अमेरिका की तरफ से देखें तो यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है। ट्रंप कहते हैं कि रूस से तेल खरीदकर भारत मॉस्को की युद्ध मशीन को पैसे दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस की कमाई कम हो, ताकि यूक्रेन में युद्ध जल्दी खत्म हो। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवarro ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो 25 प्रतिशत टैरिफ कम हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी डॉलर से रूसी तेल खरीद रहा है, जो अमेरिका के लिए समस्या है।

कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ इस फैसले का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि यह टैरिफ भारत को दबाव में लाएगा और रूस की मदद बंद करने पर मजबूर करेगा। अमेरिका पहले से ही चीन पर 30 प्रतिशत, वियतनाम पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगा चुका है। भारत और ब्राजील पर 50 प्रतिशत सबसे ज्यादा है। वजह यह कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, जो अमेरिकी डॉलर की जगह नई मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने फरवरी में ब्रिक्स को “छोटा समूह” कहा था, जो “जल्दी खत्म हो जाएगा”। उन्होंने धमकी दी कि अगर ब्रिक्स नई मुद्रा बनाएगा, तो 100 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।

लेकिन सभी अमेरिकी इससे सहमत नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि यह टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगा पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय सामान जैसे कपड़े, गहने, दवाएं महंगे हो जाएंगे। एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी परिवारों को सालाना 2400 डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। गरीब परिवारों पर इसका असर तीन गुना ज्यादा होगा। अर्थशास्त्री कहते हैं कि इससे अमेरिका का जीडीपी 432 अरब डॉलर कम हो सकता है। ट्रंप की नीति को “आर्थिक ब्लैकमेल” कहा जा रहा है। क्या यह रूस को कमजोर करेगा? या सिर्फ अमेरिका-भारत संबंध खराब करेगा? ये बातें हमें बताती हैं कि बड़े फैसले कितने जटिल होते हैं। अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन क्या यह उल्टा पड़ सकता है?

भारत पर क्या पड़ेगा असर? हमारी प्रतिक्रिया

भारत के लिए यह टैरिफ बड़ा झटका है। हमारे 87 अरब डॉलर के निर्यात का 55 प्रतिशत प्रभावित होगा। सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, गहने, चमड़ा, केमिकल, ऑटो पार्ट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जेफरीज के क्रिस वुड कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 55-60 अरब डॉलर का नुकसान होगा। जीडीपी 0.3 से 0.5 प्रतिशत कम हो सकता है। रुपया कमजोर हो सकता है। छोटे निर्यातकों और नौकरियों पर असर पड़ेगा।

लेकिन भारत पीछे नहीं हट रहा। सरकार ने कहा कि हम रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे, क्योंकि इससे ऊर्जा कीमतें कम रहती हैं। युद्ध के बाद रूस से तेल आयात बढ़ा है। अब तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि टैरिफ के बावजूद रूसी तेल आयात 10-20 प्रतिशत बढ़ेगा। साथ ही, भारत अमेरिकी तेल भी ज्यादा खरीद रहा है, क्योंकि कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं। इससे व्यापार घाटा कम हो सकता है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि भारत को रूसी तेल पर दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि हम सबसे अच्छा सौदा ढूंढेंगे।

भारत ने टैरिफ को अनुचित बताया और बातचीत की कोशिश कर रहा है। हम ब्रिक्स में सक्रिय हैं, जहां एकजुट होकर ऐसे फैसलों की निंदा की गई। ब्रिक्स ने कहा कि एकतरफा टैरिफ व्यापार को बिगाड़ते हैं और डब्ल्यूटीओ नियमों के खिलाफ हैं। भारत नए बाजार ढूंढ रहा है, जैसे ब्रिक्स के बाकी देश। चीन से रिश्ते सुधार रहे हैं। विदेश मंत्री वांग यी तीन साल बाद भारत आए। चीनी कंपनियां भारत में निवेश कर सकती हैं, जिससे तकनीक मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह मौका है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? छोटे व्यवसायों को मदद की जरूरत है। यह स्थिति हमें बताती है कि विविधता कितनी जरूरी है। एक बाजार पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। भारत की रणनीति संतुलित है – अमेरिका से दोस्ती रखो, लेकिन अपनी आजादी भी।

ब्रिक्स की ताकत बढ़ रही है: नई दुनिया की शुरुआत?

यह टैरिफ ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है। वोल्फ कहते हैं कि अमेरिका ब्रिक्स को “हॉटहाउस” में विकसित कर रहा है, जो पश्चिम का विकल्प बनेगा। ब्रिक्स का जीडीपी हिस्सा बढ़ रहा है। वे नई विकास बैंक बना रहे हैं, डॉलर की जगह नई मुद्रा पर विचार कर रहे हैं। चीन का क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टम और ब्रिक्स पे जैसे कदम डॉलर पर निर्भरता कम करेंगे। ट्रंप की धमकी से ब्रिक्स एकजुट हुआ। 2025 के ब्रिक्स समिट में 126 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें व्यापार और एआई पर सहयोग। उन्होंने टैरिफ की निंदा की।

कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप की नीति उल्टी पड़ रही है। भारत-चीन रिश्ते सुधर रहे हैं। ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी चीन से करीब आ रहे हैं। एसबीआई रिसर्च कहती है कि टैरिफ से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा – ज्यादा महंगाई, कम जीडीपी। ब्रिक्स देश नए बाजार बना रहे हैं। अगर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा, तो चीन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, लेकिन सभी देशों में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इससे ब्रिक्स में सहयोग बढ़ेगा। ग्लोबल साउथ मजबूत होगा।

क्या यह नई दुनिया की शुरुआत है? जहां पश्चिम का वर्चस्व कम हो? ब्रिक्स में 30 से ज्यादा देश शामिल होना चाहते हैं। लेकिन चुनौतियां हैं। ब्रिक्स में एकता की कमी है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है। फिर भी, यह बदलाव विचारणीय है। अमेरिका की नीति से क्या फायदा? या इससे बहुपक्षीय दुनिया बनेगी? ये सवाल हमें वैश्विक संतुलन पर सोचने को कहते हैं।

आगे क्या होगा? सोचने वाली बातें

यह स्थिति हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करती है। क्या अमेरिका भारत को दबा पाएगा? या भारत ब्रिक्स के साथ मिलकर नई राह बनाएगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि बातचीत से टैरिफ 15-20 प्रतिशत तक कम हो सकता है। लेकिन कृषि जैसे मुद्दे कठिन हैं। भारत को घरेलू क्षमता बढ़ानी होगी। एमएसएमई को मदद दें। विविध बाजार ढूंढें।

दुनिया बदल रही है। डेग्लोबलाइजेशन हो रहा है। देश अपनी सुरक्षा पहले सोच रहे हैं। ब्रिक्स जैसे समूह नई ताकत हैं। लेकिन क्या इससे युद्ध बढ़ेंगे? या शांति आएगी? वोल्फ कहते हैं कि यह ऐतिहासिक पल है। अमेरिका खुद को मजबूत समझ रहा है, लेकिन हंसी की बात है कि वह अपने पैर पर गोली मार रहा है। भारत की रणनीति स्मार्ट है – रूस से तेल लो, अमेरिका से बात करो, ब्रिक्स में मजबूत हो।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

हम दीवानों की क्या हस्ती, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले

हम दीवानों की क्या हस्ती,
हैं आज यहाँ, कल वहाँ चले,
मस्ती का आलम साथ चला,
हम धूल उड़ाते जहाँ चले।

आए बनकर उल्लास अभी,
आँसू बनकर बह चले अभी,
सब कहते ही रह गए, अरे,
तुम कैसे आए, कहाँ चले?

किस ओर चले? यह मत पूछो,
चलना है, बस इसलिए चले,
जग से उसका कुछ लिए चले,
जग को अपना कुछ दिए चले,

दो बात कही, दो बात सुनी;
कुछ हँसे और फिर कुछ रोए।
छककर सुख-दुःख के घूँटों को
हम एक भाव से पिए चले।

हम भिखमंगों की दुनिया में,
स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले,
हम एक निसानी-सी उर पर,
ले असफलता का भार चले।

अब अपना और पराया क्या?
आबाद रहें रुकने वाले!
हम स्वयं बँधे थे और स्वयं
हम अपने बंधन तोड़ चले।

भगवतीचरण वर्मा

वे इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग हैं ज़रूर

वे इस पृथ्वी पर
कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग हैं ज़रूर
जो इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर
कच्छपों की तरह धारण किए हुए हैं
बचाए हुए हैं उसे
अपने ही नरक में डूबने से

वे लोग हैं और बेहद नामालूम घरों में रहते हैं
इतने नामालूम कि कोई उनका पता
ठीक-ठीक बता नहीं सकता
उनके अपने नाम हैं लेकिन वे
इतने साधारण और इतने आमफहम हैं
कि किसी को उनके नाम
सही-सही याद नहीं रहते

उनके अपने चेहरे हैं लेकिन वे
एक दूसरे में इतने घुले-मिले रहते हैं
कि कोई उन्हें देखते ही पहचान नहीं पाता
वे हैं, और इसी पृथ्वी पर हैं
और यह पृथ्वी उन्हीं की पीठ पर टिकी हुई है
और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि उन्हें
रत्ती भर यह अंदेशा नहीं
कि उन्हीं की पीठ पर
टिकी हुई यह पृथ्वी।

भगवत रावत

अफगानिस्तान में कहर बनकर टूटा भूकंप

800 से ज्यादा मौतें, हजारों घायल

भारत ने जताया दुख और मदद का भरोसा

@ सौम्या चौबे

अफगानिस्तान एक बार फिर प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। रविवार की आधी रात को स्थानीय समयानुसार 11:47 बजे 6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने देश के कई प्रांतों को हिला दिया। इस भूकंप में अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।भूकंप के समय ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक धरती हिलने से मकान जमींदोज हो गए और लोग मलबे में दब गए। रातभर शहरों और गांवों में चीख-पुकार गूंजती रही। अधिकारियों का कहना है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

भूकंप का केंद्र जलालाबाद के पास

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, यह भूकंप जलालाबाद शहर से करीब 17 मील दूर आया। जलालाबाद की आबादी लगभग 2 लाख है। राजधानी काबुल से यह इलाका 150 किलोमीटर दूर स्थित है।इस झटके के बाद सोमवार सुबह फिर 4.6 तीव्रता का आफ्टरशॉक महसूस किया गया। यह झटका जमीन से लगभग 65 किलोमीटर गहराई में आया।

कुनार प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा मौतें अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुई हैं। यह इलाका पहाड़ी है और यहां पहुंच पाना बेहद कठिन है। पहाड़ों से घिरे इन गांवों तक राहत और बचाव दल आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं।भूकंप के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जिससे सड़कें बंद हो गईं। ऐसे में लोगों को निकालने के लिए हेलिकॉप्टरों की मदद ली जा रही है।

पाकिस्तान और भारत में भी महसूस हुए झटके

यह भूकंप सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देशों में भी इसके असर महसूस किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में झटके महसूस हुए। भारत में भी दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम में हल्की कंपन दर्ज की गई।

पीएम मोदी ने जताया दुख

अफगानिस्तान में आए इस भूकंप को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,"इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है।"भारत की यह संवेदना अफगान जनता के लिए बेहद राहत भरी कही जा रही है, क्योंकि तालिबान शासन के कारण वहां अंतरराष्ट्रीय मदद पहले से ही सीमित हो चुकी है।

अफगानिस्तान में लगातार आती रही आपदाएं।

अफगानिस्तान के लिए यह कोई पहली त्रासदी नहीं है।अक्टूबर 2023 में यहां 7 अक्टूबर को भयंकर भूकंप आया था। तालिबान सरकार ने दावा किया कि इसमें 4 हजार लोगों की मौत हुई थी, हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने 1500 मौतों की पुष्टि की थी।2022 में भी पूर्वी अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए।

क्यों आते हैं अफगानिस्तान में भूकंप?

भूगोल के लिहाज से अफगानिस्तान भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है।यह इलाका हिंदूकुश पर्वतमाला का हिस्सा है, जो हमेशा सक्रिय रहती है।अफगानिस्तान, भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित है।यहां की फॉल्ट लाइन हेरात तक जाती है। जब प्लेट्स आपस में टकराती या खिसकती हैं तो बड़े पैमाने पर भूकंप आते हैं।इसी वजह से हर साल इस इलाके में कई छोटे और बड़े भूकंप दर्ज किए जाते हैं।

राहत और बचाव में मुश्किलें

भूकंप प्रभावित इलाके ज्यादातर पहाड़ी और दुर्गम हैं। रात के समय बिजली कट गई और संचार नेटवर्क भी ठप हो गया। हेलिकॉप्टर और सेना की मदद से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, लेकिन मलबे में दबे लोगों को निकालना बेहद कठिन साबित हो रहा है।स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि हजारों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कई लोग अब भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं।

अंतरराष्ट्रीय मदद की जरूरत

तालिबान सरकार ने अब तक नुकसान का आधिकारिक ब्यौरा साझा नहीं किया है। हालांकि प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूर्वी प्रांतों में गंभीर जान-माल का नुकसान हुआ है।संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को भारी मानवीय सहायता की जरूरत पड़ेगी।

अफगानिस्तान बार-बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता है, लेकिन वहां की सरकार और प्रशासन आपदा प्रबंधन के लिहाज से अभी भी बेहद कमजोर है। सीमित संसाधन और राजनीतिक अस्थिरता राहत कार्य को और कठिन बना देती है।विशेषज्ञ मानते हैं कि अफगानिस्तान को अब भूकंप-प्रवण इलाकों में मकानों की भूकंप-रोधी तकनीक से मरम्मत करनी होगी और लोगों को जागरूक करना होगा।

तभी आने वाले समय में ऐसी बड़ी त्रासदियों से होने वाला नुकसान कम किया जा सकेगा।रविवार की रात आया यह भूकंप अफगानिस्तान के लिए एक और गहरी चोट बन गया है। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं और सैकड़ों अपनों को खो चुके हैं। इस त्रासदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान कितना असहाय हो जाता है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

पेपर लीक से रद्द हुई एसआई भर्ती

एसआई भर्ती-2021 पर हाई कोर्ट की सख्ती, लाखों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में

@ आनंद मीणा

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 एक बार फिर चर्चा में है। लाखों युवाओं का भविष्य जिस भर्ती से जुड़ा था, अब वह कानूनी दांवपेंच और राजनीतिक बयानबाजी में उलझ गई है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने पेपर लीक और गड़बड़ियों को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि अदालत ने परीक्षा पूरी तरह रद्द नहीं की है, बल्कि कुछ विशेष टिप्पणियाँ (ऑब्जर्वेशन) भेजी हैं।

कानून मंत्री की सफाई

राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि मीडिया में फैली खबरें सही नहीं हैं। उनके मुताबिक, "न्यायालय ने एसआई भर्ती को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने केवल कुछ गंभीर अनियमितताओं पर अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जिन्हें सरकार ने गंभीरता से लिया है।"उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने परीक्षा में गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार के समय जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी, उनकी भी जांच जारी है।

अभ्यर्थियों की दुविधा

इस परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों में भारी असमंजस है। लाखों युवाओं ने सालों की मेहनत इस परीक्षा में लगाई थी।कोई महीनों तक कोचिंग लेकर तैयारी कर रहा था।कई अभ्यर्थियों ने नौकरी छोड़कर परीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच यह उम्मीद लगाई थी कि पुलिस सेवा में जगह मिलेगी।लेकिन अब परीक्षा रद्द होने की खबरों से उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर दोष किसी और का है तो उनकी मेहनत क्यों बेकार जाए?

क्यों रद्द हुई भर्ती?

एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में शुरू से ही गड़बड़ियों की खबरें आती रही थीं।परीक्षा के तुरंत बाद ही पेपर लीक की चर्चाएँ शुरू हो गई थीं।कई जिलों से अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए।जांच हुई तो वाकई पेपर लीक का मामला सामने आया।इन्हीं कारणों से राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल में यह भर्ती रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट का मानना था कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं रही तो लाखों उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।

859 पदों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन

राजस्थान सरकार ने साल 2021 में सब-इंस्पेक्टर (SI) के कुल 859 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में पहुँची।परीक्षा में भी भारी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए।भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी कि तभी पेपर लीक का मामला सामने आ गया।

अदालत की भूमिका

हाई कोर्ट ने हाल में दिए अपने आदेश में कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ किया कि निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली लोकतंत्र में युवाओं के भरोसे का सवाल है। इसलिए इस परीक्षा को रद्द करना ही न्यायसंगत होगा।हालांकि सरकार का कहना है कि अदालत ने "रद्द" शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि यह कहा है कि अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई हो।

राजनीतिक रंग

जैसा कि अक्सर राजस्थान में होता है, यह मुद्दा भी राजनीतिक रंग लेने लगा है।कांग्रेस और बीजेपी एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं।बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने भर्तियों को पारदर्शी तरीके से कराने में नाकामी दिखाई है।

वहीं, कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनकी सरकार गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।कानून मंत्री जोगाराम पटेल का यह बयान भी इसी राजनीतिक खींचतान का हिस्सा माना जा रहा है।

अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

सबसे ज्यादा निराशा उन अभ्यर्थियों में है जो इस परीक्षा की तैयारी में लगे थे।सोशल मीडिया पर कई छात्र गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।जयपुर और अन्य जिलों में भी किया।उनका कहना है कि सरकार और अदालत दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दोष उम्मीदवारों का समय और मेहनत बर्बाद न हो।कई उम्मीदवारों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है, ताकि सभी को समान अवसर मिले।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भर्ती का भविष्य क्या होगा।क्या सरकार नई परीक्षा कराएगी?क्या दोषियों पर सख्त सजा होगी?या फिर उम्मीदवारों को और इंतजार करना पड़ेगा?अभी तक सरकार ने साफ तौर पर नहीं बताया है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। कानून मंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि उम्मीदवारों के हित सुरक्षित रहेंगे।राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 युवाओं के सपनों की परीक्षा थी, जो अब विवाद और कानूनी उलझनों में फंस गई है। अदालत का आदेश और सरकार की सफाई के बाद भी तस्वीर साफ नहीं है।

भारत और जापान का नया दौर

मोदी-इशिबा की मुलाकात

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जापान का दौरा किया। यह दौरा 29 अगस्त 2025 को हुआ था। वहाँ वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा से मिले। दोनों नेताओं ने भारत-जापान के बीच 15वें सालाना समिट में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए। जापान ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने का वादा किया। यह रकम करीब 6 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। मोदी जी ने दोनों देशों के लिए अगले 10 साल का रोडमैप बताया। उन्होंने इशिबा जी को भारत आने का न्योता भी दिया। यह सब कुछ टोक्यो में हुआ। दोनों देशों के रिश्ते अब और मजबूत हो रहे हैं। लेकिन क्या यह निवेश वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई देगा? आइए, इस पर गौर करें।

यह खबर इंटरनेट पर कई जगहों से आई है। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में। वहाँ बताया गया कि मोदी जी ने कहा, "हमने भारत में जापान से अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा है।" यह रकम डॉलर में करीब 68 बिलियन है। रुपये में देखें तो 6 लाख करोड़ से थोड़ा कम, लेकिन मीडिया में इसे 6 लाख करोड़ ही कहा जा रहा है। दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़े थे। मोदी जी ने इशिबा जी से कहा कि भारत और जापान मिलकर एशियन सेंचुरी को आकार देंगे। मतलब, एशिया का भविष्य हम तय करेंगे। यह बातें सुनकर लगता है कि दोनों देश अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सुरक्षा और तकनीक में भी साथ चलेंगे। लेकिन क्या वैश्विक चुनौतियाँ, जैसे अमेरिका के टैरिफ, इस पर असर डालेंगी?

इस दौरे से पहले दोनों देशों के रिश्ते पहले से मजबूत थे। 10 साल पहले ही भारत-जापान के संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का नाम दिया गया था। अब यह नया रोडमैप उस पर और काम करेगा। मोदी जी ने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कैपिटल सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि गुणा होता है। मतलब, निवेश से फायदा कई गुना मिलेगा। जापानी कंपनियों ने पहले ही भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश किया है। पिछले 2 सालों में 13 बिलियन डॉलर का प्राइवेट निवेश आया। यह सब देखकर लगता है कि जापान भारत को बड़ा बाजार मानता है। लेकिन क्या यह निवेश आम आदमी तक पहुँचेगा? नौकरियाँ बढ़ेंगी या सिर्फ बड़े शहरों में सिमट कर रह जाएगा?

6 लाख करोड़ का निवेश: क्या और कैसे होगा?

अब बात करते हैं मुख्य निवेश की। जापान ने 10 ट्रिलियन येन भारत में लगाने का फैसला किया है। यह अगले 10 सालों में होगा। मोदी जी ने इसे रोडमैप का हिस्सा बताया। यह रकम सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा जी ने कहा, "भारत का बड़ा बाजार जापान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।" दोनों देशों ने 13 एमओयू साइन किए। इनमें डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, मिनरल रिसोर्सेज, कल्चरल एक्सचेंज शामिल हैं। एक बड़ा प्लान है 500,000 लोगों का आदान-प्रदान। इसमें 50,000 स्किल्ड वर्कर्स भारत से जापान जाएँगे।

यह निवेश पहले के लक्ष्य से दोगुना है। पहले 5 ट्रिलियन येन का टारगेट था। अब 10 ट्रिलियन। लेकिन क्या यह आसान होगा? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को देखें तो मुंबई-अहमदाबाद लाइन में देरी हुई है। लागत बढ़ गई। ऐसे में नया निवेश समय पर आएगा? फिर भी, मोदी जी ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई। यह सब निवेशकों को आकर्षित करेगा। जापानी कंपनियाँ स्टील, एआई, स्पेस, एजुकेशन में एमओयू साइन कर रही हैं।

इंडिया-जापान इकोनॉमिक फोरम में मोदी जी ने कहा, "भारत दुनिया की ग्रोथ का 18% योगदान दे रहा है। जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।" उन्होंने 5 क्षेत्र बताए: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की टैलेंट मिलकर कमाल करेगी। लेकिन क्या पर्यावरण पर असर पड़ेगा? ग्रीन एनर्जी पर फोकस है, तो शायद अच्छा हो। वैश्विक स्तर पर ट्रंप के टैरिफ से दोनों देश प्रभावित हैं। भारत पर 50% टैरिफ, जापान की कारों पर 25%। ऐसे में साथ मिलकर सामना करेंगे।

यह निवेश एसएमई और स्टार्टअप्स को जोड़ेगा। इंडिया कंसाई बिजनेस फोरम और क्यूशू फोरम शुरू होंगे। ग्रासरूट लेवल पर बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन क्या छोटे उद्यमी इसका फायदा उठा पाएँगे? ट्रेनिंग और सपोर्ट चाहिए। कुल मिलाकर, यह निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। जीडीपी बढ़ेगी, नौकरियाँ आएँगी। लेकिन बैलेंस्ड तरीके से होना चाहिए, ताकि अमीर-गरीब का फर्क न बढ़े।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र: तकनीक से सुरक्षा तक

रोडमैप में कई क्षेत्र हैं। सबसे पहले आर्थिक पार्टनरशिप। निवेश बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। अभी सालाना ट्रेड 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जापान के फेवर में। अब बैलेंस करने की कोशिश। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मा, आईसीटी, क्लीन एनर्जी पर फोकस। जापान-इंडिया एआई इनिशिएटिव शुरू होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डेटा सेंटर्स, एआई गवर्नेंस पर काम।

तकनीक और इनोवेशन में क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, स्पेस। इसरो और जैक्सा ने चंद्रयान-5 के लिए अरेंजमेंट साइन किया। क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर डिक्लेरेशन। हेल्थ में सहयोग बढ़ेगा। मोबिलिटी में हाई-स्पीड रेल, लॉजिस्टिक्स। 2047 तक भारत 7000 किलोमीटर हाई-स्पीड रेल नेटवर्क बनाएगा। जापान मदद करेगा। लेकिन जैसा कि पहले कहा, देरी हो रही है। क्यों? जमीन अधिग्रहण, लागत। इन चुनौतियों पर विचार करना चाहिए।

सुरक्षा का हिस्सा भी बड़ा है। दोनों देश इंडो-पैसिफिक में शांति चाहते हैं। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी पर चिंता जताई। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि फ्री, ओपन, रूल्स-बेस्ड इंडो-पैसिफिक चाहिए। डिफेंस ड्रिल्स बढ़ेंगी। टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी पर साथ काम। मोदी जी ने रूस-यूक्रेन पर भारत की स्टैंड बताया। मानवीय आधार पर मदद। क्या यह ग्लोबल पीस में मदद करेगा?

पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज। कल्चर, एजुकेशन। बौद्धizm का इतिहास याद किया, जो 6ठी सदी में जापान पहुँचा। स्टेट-प्रिफेक्चर एंगेजमेंट। लोकल लेवल पर टाईअप। कुल मिलाकर, यह रोडमैप बहुआयामी है। लेकिन क्या सभी क्षेत्रों में बराबर प्रोग्रेस होगा? तकनीक में तेजी, लेकिन पर्यावरण में धीमा न हो जाए। सोचने वाली बात है कि कैसे बैलेंस रखें।

रणनीतिक महत्व: एशिया और दुनिया के लिए

भारत और जापान दो बड़े लोकतंत्र हैं। दोनों की पार्टनरशिप ग्लोबल पीस के लिए जरूरी। मोदी जी ने कहा, "हम एशियन सेंचुरी को शेप देंगे।" इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए स्प्रिंगबोर्ड बनेगा जापानी बिजनेस के लिए। लेकिन चीन की चुनौतियाँ हैं। सी बॉर्डर पर टेंशन। दोनों देश मिलकर सामना करेंगे। क्वाड में भी साथ हैं।

ग्लोबल कंटेक्स्ट में ट्रंप के टैरिफ। भारत पर 50%, जापान पर 25% कार टैरिफ। ऐसे में सप्लाई चेन मजबूत करने की जरूरत। जापान इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा। मेक इन इंडिया को बूस्ट। लेकिन क्या यह आत्मनिर्भर भारत को मदद देगा या विदेशी निर्भरता बढ़ाएगा? बैलेंस्ड व्यू: फायदे ज्यादा लगते हैं, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें।

मोदी का दौरा चीन के SCO समिट से पहले। वहाँ शी जिनपिंग और पुतिन से मिलेंगे। बॉर्डर क्लैश के बाद रिलेशंस ठीक हो रहे हैं। क्या जापान के साथ टाईअप चीन को मैसेज है? विचार करें कि कैसे बैलेंस रखें। कुल मिलाकर, यह पार्टनरशिप रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। लेकिन क्या आम लोग इसका फायदा महसूस करेंगे? नौकरियाँ, बेहतर जीवन।

भविष्य की राह: न्योता और उम्मीदें

मोदी जी ने इशिबा जी को भारत आने का न्योता दिया। खासकर फरवरी 2026 के एआई इम्पैक्ट समिट में। यह समिट भारत होस्ट करेगा। दोनों नेता चिप फैक्ट्री और शिंकानसेन फैक्ट्री घूमने वाले थे। यह दिखाता है कि प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ेगा।

रोडमैप से उम्मीदें बड़ी हैं। निवेश से जीडीपी ग्रोथ, इनोवेशन। लेकिन चैलेंजेस हैं: ग्लोबल अनसर्टेन्टी, इंप्लीमेंटेशन। क्या 10 साल में सब पूरा होगा? पिछले अनुभव से सीखें। जैसे बुलेट ट्रेन। फिर भी, पॉजिटिव नोट पर, मोदी जी ने कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट विनिंग कॉम्बिनेशन है। क्या यह सच साबित होगा? समय बताएगा। लेकिन दोनों देश मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। सोचिए, अगर यह सफल हुआ तो एशिया कैसा होगा। शांत, समृद्ध। यह सब देखकर लगता है कि भारत-जापान के रिश्ते नई ऊँचाई पर हैं। आम आदमी के लिए यह अच्छी खबर है। लेकिन निगरानी रखें कि फायदे सब तक पहुँचें।

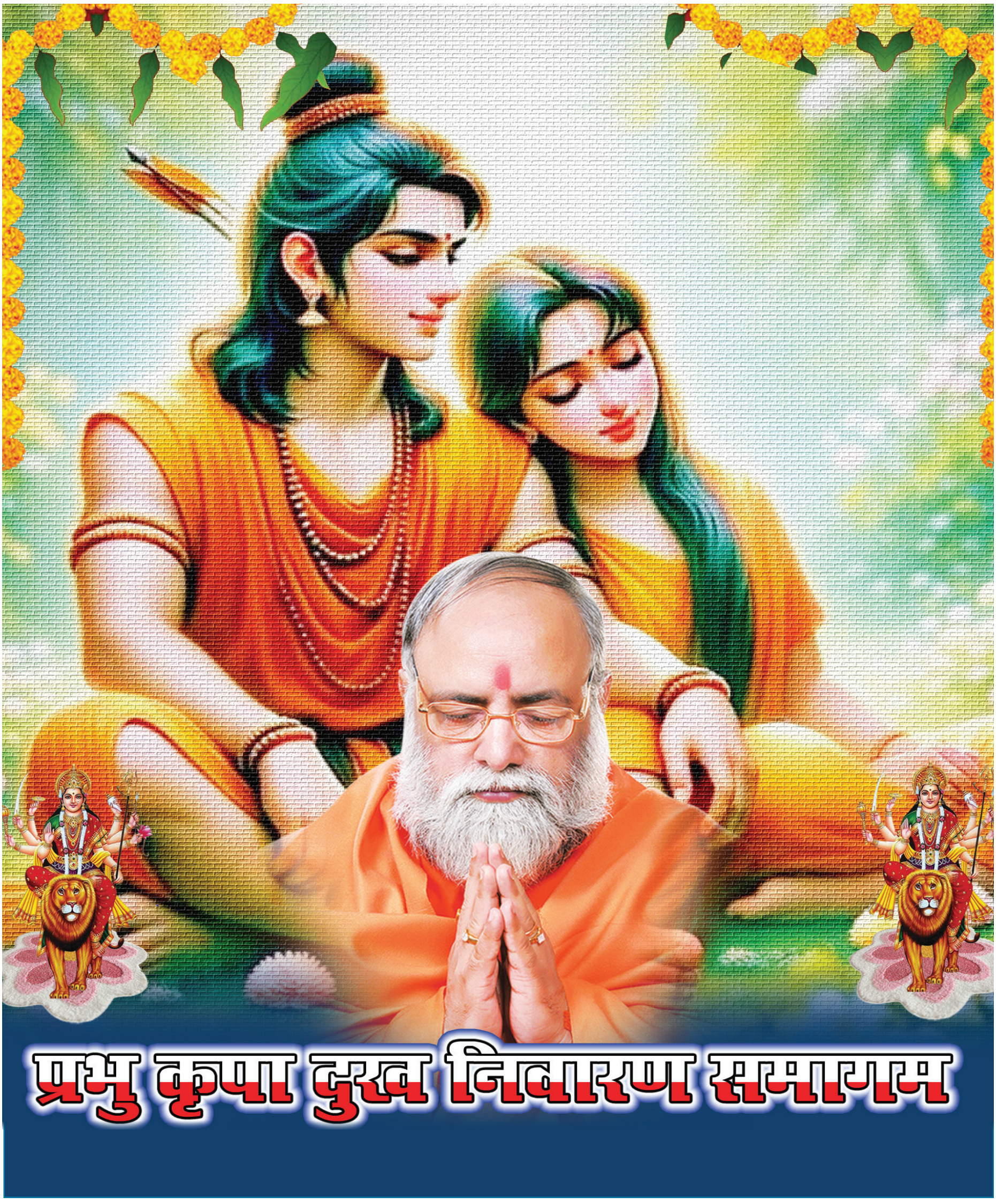
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries